सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 257, नई दिल्ली । बुधवार, 27 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

समुद्र में चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, समुद्र अपनी शांति कभी नहीं छोड़ता

03 अरविंद केजरीवाल से मिले हेमंत सोरेन, शपथ ग्रहण समारोह का दिया न्योता
06 नीट यूजी 2025 के ऑनलाइन मोड में स्थांतरित होने की संभावना
08 पीएम मोदी ओड़िशा में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सम्मेलन में भाग लेंगे

बुराड़ी/ झूलझूली वाहन जांच शाखा विवाद

संजय बाटला

नई दिल्ली। बुराड़ी / झूलझूली जांच शाखा विवाद में घिरे वाहनों के मालिकों ने आज अवतार सिंह पूर्व मेयर से मुलाकात कर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष और उपराज्यपाल दिल्ली से इस विवाद को खत्म करवाने के लिए आगे आ कर दिल्ली के व्यवसायिक वाहन मालिकों को परेशानियों से मुक्त करवाने की अपनी बात रखी ।

इस बैठक में सरदार अवतार सिंह, पूर्व महापौर, उत्तरी दिल्ली (एमसीडी), विनोद नेगी अध्यक्ष ग्रामीण सेवा, किशन कुमार छाबड़ा, राजेश कक्कड़, सुभाष त्यागी, देवेंद्र यादव, तुषार अरोड़ा, यशपाल सिंह और अन्य कई वाहन चालकों ओर मालिकों ने हिस्सा लिया।

उन्होंने बताया दिल्ली में वाहन फिटनेस जांच को लेकर फिर से विवाद खड़ा है। झूलझूली के स्वचालित वाहन जांच केंद्र पर बढ़ते दबाव और कानून-व्यवस्था की समस्याओं के समाधान किए बिना दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी ने वाहन जांच का काम फिर से बुराड़ी वाहन जांच शाखा से परिवर्तित कर झूलझूली वाहन जांच शाखा में शुरू करने का आदेश दे दिया है।

उन्होंने बताया इस फैसले ने 2018 और 2019 के दौरान लिए गए फैसलों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।

आइए जानते हैं, आखिर क्यों दिल्ली सरकार को झूलझूली से काम हटाकर उस समय बुराड़ी में वापस लाने का फैसला करना पड़ा था।

झूलझूली वाहन जांच केंद्र पर काम का दबाव नियंत्रण से बाहर हो गया था। झूलझूली में प्रतिदिन 400 वाहनों की जांच हो सकती है, जिसमें हर वाहन के फिटनेस टेस्ट में औसतन 2.5 घंटे लगते हैं। इस वजह से वाहनों के फिटनेस टेस्ट के लिए 22 दिन तक का वेटिंग पीरियड हो गया। इसके अलावा, झूलझूली के आस-पास कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्याएं भी आ रही थीं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुंडे वाहन चालकों से अवैध वसूली करते थे। इस वजह से दो लाइसेंसिंग अधिकारियों ने भी इस्तीफा दे दिया था और परिवहन विभाग द्वारा दो एफआईआर भी दर्ज की हुई है।

उन्होंने बताया की 2018 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुराड़ी आरटीओ को भ्रष्टाचार का अड्डा करार देते हुए बंद करने का आदेश कर दिया था। इसके बाद बुराड़ी में वाहन जांच शाखा को बंद कर 37 एकड़ के भूखंड पर एक आधुनिक प्रशिक्षण-सह-परीक्षण संस्थान बनाने की योजना बनाई गई थी।

उन्होंने बताया तब भी बुराड़ी में दो इकाइयां थीं - एक ऑटो-रिक्शा यूनिट और दूसरी वाणिज्यिक वाहन निरीक्षण यूनिट। ऑटो-रिक्शा यूनिट को 13 आरटीओ में विभाजित किया गया, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से बुराड़ी यूनिट को चालू करना पड़ा और मई 2019 में घोषित योजना को रोक कर वापिस वाहनों की जांच शुरू कर दी गई थी।

उनका कहना है कि सरकार और परिवहन विभाग 2018 से ही अच्छी तरह जानते थे कि झूलझूली केंद्र वाहनों की जांच का भार संभालने में अक्षम है। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान किए बिना वाहनों को झूलझूली भेजने का आदेश दिया गया।

संगठन ने मांग की है कि जब तक और ऑटोमेटिक वाहन जांच मशीनें नहीं लग जाती तब तक बुराड़ी में वाहनो की जांच तुरंत शुरू करने के आदेश जारी किए जाए और उन अधिकारियों पर भी निष्पक्ष जांच शाखा द्वारा जांच कराई जाए जिन्होंने यह आदेश जारी किए।

बुराड़ी और झूलझूली के इस विवाद ने एक बार फिर दिल्ली सरकार और दिल्ली परिवहन विभाग की नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या दिल्ली सरकार इन समस्याओं का कोई स्थायी समाधान निकाल पाएगी, या ये विवाद यूं ही चलते रहेंगे ? इसे लेकर हम आपको अपडेट देते रहेंगे।

बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

नमस्कार जी मैं आर के शर्मा आपसे एक निवेदन करता हूं 27 नवंबर 2024 को अपना अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अधिवेशन राजा राममोहन राय ऑडिटोरियम 12 दिगंबर मार्ग आईटीओ दिल्ली में होना है दोस्त देश के 20 करोड़ लोगों को रोजगार देकर पालन पोषण करने तथा देश की उन्नति में दिन रात मेहनत करके अहम भूमिका निभाने वाली अपनी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है और ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर और उससे जुड़े व्यवसाय वालों की सरकार, प्रशासन एवं आम आदमी के सामने कोई इज्जत भी नहीं है इसके लिए हमें पूरे देश के ट्रांसपोर्टरों को इकट्ठा करके सरकार के अपनी मांगे मनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, अधिवेशन में पूरे देश से हर तरह के ट्रांसपोर्टर भाई भाग ले रहे हैं तथा सब मिलकर कोई ठोस निर्णय भी लेंगे इस लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है ट्रांसपोर्ट बिरादरी की भलाई के लिए एक दिन के लिए आप खुद आए या अपने किसी एक साथी को फोन करके या मैसेज करके अधिवेशन में आने के लिए जरूर प्रेरित करें मै कल आपका या आपके द्वारा भेजे गए किसी ट्रांसपोर्ट भाई का इंतजार करूंगा कुछ पूछना हो तो ऊपर दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे बनने से कालिंदी कुंज चौक पर दिनभर लगता है भीषण जाम, एनसीआर के लोग परेशान

दक्षिणी दिल्ली के मीठापुर के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के शुरू होने के बाद से कालिंदी कुंज चौक पर दिनभर भीषण जाम लगता है। छह लेन का हाईवे खुलने से दिल्ली सहित राजस्थान और हरियाणा के वाहन चालक कालिंदी कुंज चौक से मीठापुर रोड का इस्तेमाल कर आवाजाही कर रहे हैं। वहीं अब फरीदाबाद बदरपुर और मीठापुर आने-जाने वाले लोगों को परिशानी हो रही है।

दिल्ली। बदरपुर विधानसभा के मीठापुर चौक पर छह लेन का हाईवे शुरू होने से हरियाणा और राजस्थान जाने वाले वाहन चालकों को जाम से काफी हद तक राहत मिल गई। वह सीधा कालिंदी कुंज चौक से हाईवे पर जाकर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं।

दूसरी तरफ इस रूट पर वाहनों की संख्या बढ़ने से कालिंदी कुंज चौक पर दिनभर जाम लगने लगा है। सुबह और शाम को लालबत्ती से भी यातायात सुचारू नहीं हो पाता। यातायात पुलिस को खुद ही मोर्चा संभालना पड़ रहा है। इसके बाद भी भयंकर जाम लग रहा है।

12 नवंबर को मीठापुर चौक के पास छह लेन के हाईवे का उद्घाटन किया गया था। जो लोग नोएडा आने-जाने के लिए मथुरा रोड का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वह इस हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं।

फरीदाबाद और राजस्थान आने-जाने वाले वाहन चालक मथुरा रोड पर न जाकर कालिंदी कुंज से ही मीठापुर रोड से हाईवे पर जा रहे हैं। ऐसे में हाईवे और कालिंदी कुंज चौक से जुड़ने वाले मीठापुर रोड पर यातायात का दबाव बढ़ गया है।

इससे कालिंदी कुंज चौक पर सुबह से शाम तक भयंकर जाम लग रहा है। नोएडा और फरीदाबाद की तरफ से आने वाला यातायात कालिंदी कुंज चौक पर आमने-सामने आ जाता है। ऐसे में पूरा क्षेत्र चौक हो जाता है।

मीठापुर से आने वाले रोड पर आठ गुणा बढ़े वाहन

यातायात पुलिस का दावा है कि हाईवे शुरू होने से मीठापुर रोड पर करीब आठ गुणा वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। पहले यहां से दिनभर करीब 20 से 30 हजार वाहन गुजरते थे। अब इस मार्ग से प्रतिदिन करीब डेढ़ लाख वाहन चालक गुजर रहे हैं। इनमें अधिकतर राजस्थान, फरीदाबाद, बदरपुर, मीठापुर आने-जाने वाले शामिल हैं।

15 से 55 सेकेंड करना पड़ा लालबत्ती का समय

यातायात पुलिस ने कालिंदी कुंज चौक पर यातायात को सुचारू करने के लिए मीठापुर लालबत्ती का समय भी बढ़ा दिया है। पहले 15 सेकेंड की लालबत्ती होती थी। अब इसे 55 सेकेंड कर दिया गया है। इसके बावजूद जाम से कोई राहत नहीं मिल रही है।

प्रतिदिन होती है करीब चार लाख वाहनों की आवाजाही

यातायात पुलिस के अनुसार कालिंदी कुंज चौक से प्रतिदिन करीब चारी लाख वाहनों की आवाजाही होती है। यहां से नोएडा, सरिता विहार फ्लाईओवर, मदनपुर खादर, फरीदाबाद, राजस्थान के लिए वाहन गुजरते हैं। पुलिस का कहना है कि सुबह और शाम को भीषण जाम लगता है। नोएडा से आने वाले यातायात के लिए 155 सेकेंड की लालबत्ती करने पर भी स्थिति सामान्य नहीं होती।

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे से जुड़ जाता है हाईवे

हाईवे शुरू होने से पहले नोएडा से फरीदाबाद जाने वाले वाहन चालक मथुरा रोड का इस्तेमाल करते थे। अब वह हाईवे का इस्तेमाल कर फरीदाबाद, हरियाणा के पलवल, सोहना व राजस्थान के दौसा सहित अन्य जगह जा रहे रहे हैं। चूंकि यह हाईवे आगे जाकर दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे से जुड़ जाता है।

इस वजह से यातायात का दबाव बढ़ा है। हाईवे खुलने से पहले सोहना जाने के लिए अभी ढाई घंटे का समय लगता है, लेकिन अब 25 मिनट में सोहना पहुंच रहे हैं।

दिल्ली में यशोभूमि मेट्रो स्टेशन का बदलेगा नाम? ग्रामीणों का प्रदर्शन तेज, बताई अपनी मांग

परिवहन विशेष न्यूज

द्वारका स्थित यशोभूमि मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर भरथल गांव के नाम पर करने की मांग को लेकर पालम 360 के बैनर तले ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि मेट्रो भरथल गांव की जमीन पर है और सरकार ने जबरन कम कीमत पर जमीन ली है लेकिन गांव की पहचान नहीं छीन सकती। प्रदर्शनकारियों ने म्यूटेशन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की भी मांग की।

नई दिल्ली। द्वारका स्थित यशोभूमि मेट्रो स्टेशन का नाम बदला जाए, इस मांग को लेकर पालम 360 के बैनर तले मेट्रो स्टेशन के नजदीक की ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पालम 360 के प्रधान चौ सुरेंद्र सोलंकी व कई अन्य लोग मौजूद रहे।

प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यशोभूमि मेट्रो का नाम भरथल गांव के नाम पर किया जाए क्योंकि यह मेट्रो भरथल गांव की जमीन पर है। सरकार ने भरथल गांव की जमीन भले ही गांव वालों से जबरन औने पौने भाव में लिया लेकिन गांव की पहचान नहीं छीन सकती।

आखिरी सांस तक मजबूती से लड़ा जाएगा अस्तित्व की लड़ाई

ऐसा होने हरगिज नहीं दिया जाएगा। भरथल हो या कोई अन्य गांव, देहात अपने अस्तित्व के लिए आखिरी सांस तक मजबूती से लड़ेगा। यह कहा गया कि गांव की जमीनों पर सभी सरकारी संस्थान बनते हैं, मेट्रो, हाईवे, एयरपोर्ट बनते हैं और गांवों का ही नाम वहां से गायब कर दिया जाता है।

ऐसा एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। इस दौरान एक बार फिर म्यूटेशन की प्रक्रिया को फिर से आरंभ और आसान करने की मांग उठाई गई।

हरिवंशराय बच्चन के जन्मदिवस 27 नवंबर पर विशेष लेख

बने रहे यह पीने वाले, बनी रहे यह मधुशाला

डॉ. मुकेश "कबीर"-विनायक फीचर्स

हरिवंश राय बच्चन उन गिने चुने कवियों में से हैं जिनका गद्य भी उतना ही सशक्त था जितना कि पद्य। उनके बारे में हुल्लड़ मुरादाबादी का दोहा भी इसी तरह का है-

गद्य पद्य में एक सी जो भी कलम चलाए,
इस दुनिया में वोही शख्स हरिवंश कहलाए।

हुल्लड़ जी की यह पंक्तियां बिल्कुल सही भी हैं ,यही कारण है कि बच्चन एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनको पद्य और गद्य दोनों रचनाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। उनके कविता संग्रह *दो चट्टानें* को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और गद्य रचना *दशद्वार से सोपान तक* को सरस्वती सम्मान मिला। *दशद्वार से सोपान तक* उनकी आत्मकथा है जो बहुत रोचक है और एक तरह से आत्मकथा लिखने वालों के लिए स्कूल की तरह है । यह कृति सच्चाई,मर्यादा और सरलता का अद्भुत संगम है।आमतौर पर लोग आत्मकथा लिखने में या तो बहुत विनम्र,बेचारे हो जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा साहसी लेकिन बच्चन जी की आत्मकथा में संतुलन है और घटनाओं का वर्णन भी ऐसा बिन्दुवार और रोचक है कि यह गद्य भी कविता की लय और गहराई तक पहुंच जाता है,और कोई भी पढ़ने वाला बोर नहीं होता । यही बच्चन की कलम की ताकत है। यही प्रभाव उनकी कविताओं का भी है । उन्होंने बहुत सरलता से गहरी बातें कहीं हैं । यही कारण है कि उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं बल्कि उनके कई टाइटल तो आज आम जीवन के मुहावरे बन चुके हैं । जैसे *बीत गई सो बात गई* या *नीड का निर्माण* या फिर *मधुशाला*। मधुशाला उनकी सबसे चर्चित कृति है , मधुशाला और बच्चन जी एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं,हालांकि जब यह लिखी गई थी तब इसका विरोध भी हुआ था लेकिन बाद में यह एक क्लासिक रचना मानी जाने लगी। उन्होंने मधुशाला का पहली बार पाठ बनारस हिंदू विश्व विद्यालय में किया था,जहां वो प्राध्यापक थे। जिस दिन मधुशाला उन्होंने सुनाई तब छात्र और श्रोताओं की संख्या कम थी इसलिए ज्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई लेकिन जिन गिने चुने छात्र और स्टॉफ ने यह रचना सुनी थी उन्होंने इसकी इतनी तारीफें कर दीं कि पूरे विश्वविद्यालय में यह बात फैल गई और उस वक्त के छात्र संघ अध्यक्ष ने एक आयोजन सिर्फ बच्चन को सुनने के लिए ही किया। पब्लिसिटी खूब हो चुकी थी इसलिए हॉल खचाखच भरा था। उस वक्त कविता सुनने का क्रेज था और कवि को वैसा ही सम्मान और लोकप्रियता हासिल थी जैसी आज किसी बड़े फिल्म स्टार को या क्रिकेट स्टार को हासिल है। तब नए कवि को सुनने की उत्सुकता ज़रा ज्यादा ही होती थी इसलिए लोग इतने थे कि पैर रखने की जगह भी नहीं बची। सीढ़ियों पर भी लोग बैठ गए थे। जब बच्चन जी मंच पर आए तो उनका तालियों की गड़गड़ाहट से गर्मजोशी के सादर स्वागत हुआ। तब वो युवा तो थे ही खूबसूरत भी बहुत थे इसलिए पहला इंप्रेशन तो बहुत अच्छा पड़ा और फिर जब उन्होंने मधुशाला सुनाई तो छात्रों में अथाह उत्साह और उमंग की लहरें दौड़ने लगीं, तब छात्रों ने इसको शराब तक ही सीमित समझा, तो कई पीने वालों को तो बच्चन जी में अपना मसीहा दिखने लगा जो पीने पिलाने की सरेआम की वकालत कर रहा है। करीब दो घंटे तक बच्चन जी सुनाते रहे और कोई भी टस से मस नहीं हुआ और जब यह रचना पूरी हुई तो तालियों की गड़गड़ाहट और एक बार और की फरमाइश और स्टैंडिंग ओबेशन कुल मिलाकर सुपर हिट आयोजन और बस दो घंटे में ही बच्चन जी हीरो बन गए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में। खास बात यह कि उस ज़माने में जो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध हो जाता था उसकी चर्चा पूरे देश के साहित्य जगत में पहुंच जाती थी,यही बच्चन जी के साथ हुआ। वे बहुत ही जल्दी पूर्वांचल फिर अवध और जल्दी ही दिल्ली तक ख्यात हो गए और कवि सम्मेलनों में आमंत्रित किए जाने लगे। कवि सम्मेलन में बच्चन जी जल्दी ही इतने प्रसिद्ध हो गए कि वे कवि सम्मेलन की अनिवार्यता बन गए। उनको कवि सम्मेलनों का पहला सुपर स्टार कहा जा सकता है,क्योंकि लोग इनका इंतजार करते थे और कुछ लोग तो ढोलक,मजीरे लेकर भी आते थे ताकि बच्चन के साथ बजा सकें। बच्चन ने मधुशाला जितनी अच्छी लिखी थी उतना ही अच्छा उनका प्रस्तुतीकरण भी था,मधुर आवाज और सुरीली गायकी से ऐसा समां बंध जाता था कि पूरी पूरी रात लोग बैठकर सुनते थे । यह वह दौर था जब भारत में मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन कवि सम्मेलन ही हुआ करते थे । तब गाने वाले कवि भी बहुत कम थे । आजादी का नशा खत्म नहीं हुआ था इसलिए ज्यादातर कवि ओज सुनाते थे । तब बुलंद आवाज़ और जोश कवियों की खासियत मानी जाती थी । ऐसे दौर में बच्चन जब मधुर गायकी लेकर मंच पर आए तो पूरा माहौल ही बदल गया । इसका फायदा कवि सम्मेलनों को भी हुआ और बच्चन जी को भी,दोनों ने एक दूसरे को लोकप्रियता दिलाई। तब बच्चन जी युवाओं में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे और युवा उनकी तरह बनना चाहते थे । उन्होंने कई युवा कवियों को प्रेरित किया जो आगे जाकर बड़े कवि बने उनमें से नीरज जी भी एक हैं। नीरज ने खुद इस बात को स्वीकार किया कि बच्चन को देखकर ही मैं मंच की तरफ आकर्षित हुआ और उनको देखकर ही मैने मंच पर गीत और गाना शुरू किया,बाद की कहानी तो हम सब जानते हैं कि नीरज जी अपने गुरु से भी आगे निकल गए।नीरज जी को पहली बार मंच पर भी बच्चन जी ही लेकर गए थे,उस दिन बस में भीड़ बहुत थी बच्चन जी को तो सीट मिल गई लेकिन युवा नीरज खड़े रहे तब बच्चन जी ने युवा नीरज को अपनी गोद में बैठा लिया और तभी नीरज ने घोषणा कर दी कि मै बड़ा कवि बनूंगा ,इसका कारण पूछने पर बोले कि जो आपकी गोद में बैठ चुका हो जिसके सर पर आपका हाथ रखा जा चुका हो वो नहीं तो कौन बनेगा बड़ा कवि ? और यह बात सच साबित हुई। बहरहाल बच्चन की बात करें तो उनकी मधुशाला की लोकप्रियता देखकर उनके ही एक कलीग ने मधुशाला की पैरोडी ताड़ीशाला

लिखी लेकिन वह ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सकी । उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि बच्चन का प्रस्तुतीकरण भी कमाल का था।

बच्चन जी जितने सशक्त मंच पर थे उनका साहित्य भी उतना ही सशक्त रहा है,यह भी एक बिरली बात है जो हर कवि में नहीं होती । बच्चन जी की रचनाएं बहुत प्रेरणादायी होती हैं और साथ ही उनका मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पक्ष भी बहुत मजबूत है। मधुशाला भी शुरू में भले ही किसी कारण से लोकप्रिय हुई हो लेकिन बाद में जब इसका दार्शनिक पक्ष लोगों को समझ आया तो फिर यह पुस्तकालयों की अनिवार्यता बन गई । यहां तक कि पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को मधुशाला पढ़ने के लिए देने लगे।आज नब्बे साल बाद भी मधुशाला की बहुत सी बातें सही प्रतीत होती हैं- जैसे राह पकड़ तू एक चलाचल पा जायेगा मधुशाला,यह पंक्ति दुविधा और दोराहे की स्थिति में अच्छा समाधान देती है कि कोई भी एक निर्णय लेकर काम शुरू कर दो मंजिल मिल ही जाएगी। उनकी ₹बीत गई सो बात गई₹ तो अब एक कहावत बन चुकी है । जब भी कोई अतीत के कारण दुखी होता है तो हम उसको यही कहकर समझाते हैं, यह बच्चन जी की सरल भाषा का ही कमाल है। साहित्य में एक कहावत है कि सरल लिखना ही सबसे कठिन है और यह काम बच्चन जी ने बखूबी किया है। अपनी इसी सरलता के कारण ही वे इतने सफल भी हुए हैं क्योंकि वे जिस दौर के रचनाकार थे वह दौर ऐसे छायावादी कवियों का दौर था , जिनकी भाषा कठिन और विशुद्ध हिन्दी होती थी,जिसे आम लोग आसानी से नहीं समझ पाते थे । ऐसे दौर में बच्चन जी जब आम बोलचाल की भाषा को साहित्य में लेकर आए तो हाथों हाथ बिकने लगे और नए लोग बहुत तेजी से कविता की ओर खिंचने लगे । यह बच्चन जी की बड़ी सफलता थी कि उन्होंने आम लोगों को भी कविता और साहित्य से जोड़ दिया। बच्चन जी बहुत आधुनिक विचारों के धनी थे ।अपने वक्त से सौ साल आगे । यही कारण है कि उनके बेटे अमिताभ फिल्मों में आ सके जबकि अमिताभ बहुत पढ़े लिखे और एक्जीक्यूटिव थे लेकिन जॉब छोड़कर फिल्मों में आने का निर्णय वो भी साठ के दशक में बहुत दूरदर्शी और समय से पहले का निर्णय था । तब बच्चन जी ने न केवल इस निर्णय का स्वागत किया बल्कि अमिताभ की मदद के लिए मुंबई भी आए और अपने फिल्मी मित्रों से अमिताभ को मिलवाया भी। तब फिल्म इंडस्टी में भी बच्चन जी को जानने और चाहने वाले बहुत लोग थे।अमिताभ को उनका बेटा होने का निश्चित रूप से फायदा हुआ । उन्हें फिल्में मिलने में भी आसानी हुई और दर्शकों तक पहुंचने में भी। बाद में अमिताभ इतने बड़े स्टार बने कि बच्चन जी खुद अमिताभ के कारण जाने गए लेकिन बच्चन जी की परवरिश का ही नतीजा था कि अमिताभ इतने सफल हुए। अमिताभ के संस्कार उनकी सबसे बड़ी ताकत है जो उनको अन्य हीरोज से अलग बनाती है। बच्चन जी ने दोनों बच्चों को उस वक्त के सबसे बड़े स्कूल शेरवुड नैनीताल में पढ़ाया जहां आज भी पहुंचना आसान नहीं है। शेरवुड की शिक्षा ने अमिताभ को अभिजात्य वर्ग में आसानी से शामिल कराया। शेरवुड में पढ़ाने का निर्णय बच्चन जी की दूरदर्शिता और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है । वे जानते थे कि अच्छी शिक्षा का महत्व क्या है। खुद बच्चन जी भी बहुत एजुकेटेड थे,ऑक्सफोर्ड में पढ़े थे इसलिए उन्हें पूरब और पश्चिम दोनों सभ्यताओं की पहचान थी । संस्कारों के मामले में बच्चन जी पूरे भारतीय थे तो व्यावसायिकता के मामले में अंग्रेज। बच्चन जी बहुत मेहनती थे,काम को पूरा किए बिना विश्राम नहीं करते थे,यही गुण अमिताभ में भी देखा जा सकता है। बच्चन जी असल में जो लिखते थे वैसा ही उनका जीवन भी था । वे आदर्श की सिर्फ बातें नहीं करते थे बल्कि खुद भी अमल करते थे इसीलिए उनके पास मानव जीवन की हर समस्या का समाधान भी होता था इसका जिक्र अमिताभ ने कई बार किया है अमिताभ अपने भाषणों में अक्सर बच्चन जी का एक वाक्य दोहराया करते हैं *मन का हो तो अच्छा न हो तो और भी अच्छा* , अब तो यह वाक्य देश के हर घर में पहुंच चुका है। उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रेरक है जितना पहले था, अमिताभ तो खुद भी कहते हैं कि जब भी मैं किसी दुविधा में होता हूं तो बाबूजी की किताबें पढ़ने बैठ जाता हूं फिर मुझे समाधान भी मिल जाता है और शांति भी।बच्चन जी का साहित्य है भी ऐसा ही इसीलिए आज भी बच्चन जी उतने ही प्रासंगिक हैं। आज बच्चन जी का एक सौ पच्चीसवां जन्मदिन है । आज वे हमारे बीच नहीं है लेकिन कोई भी साहित्यकार अपने साहित्य के कारण सदैव मौजूद होता । यही कारण है कि आज सवा सौ साल बाद भी बच्चन जी उतने ही तरोताजा हैं,आज भी कहीं न कहीं उनकी रचनाओं का जिक्र जरूर होता है।उनकी रचनाओं में ताकत और गहराई बहुत है क्योंकि वे अथाह संघर्ष और त्याग का परिणाम है,,उन्होंने खुद लिखा भी है

कितने मन के महल ढहे तब खड़ी हुई यह मधुशाला और हम भी यही चाहते हैं कि यह मधुशाला हमेशा खड़ी रहे और दुनिया को प्रेरित करती रहे,उन्ही के शब्दों में उनको श्रद्धांजलि *बनें रहें यह पीने वाले बनी रहे यह मधुशाला*।(विनायक फीचर्स)(लेखक गीतकार हैं।)

इन्दौर को स्वछता की प्रतिस्पर्धा में जीत के लिए अब कठोर साधना की जरूरत है

हरिहर सिंह चौहान इन्दौर

'इन्दौर जो लगातार स्वछता में सात बार अव्वल आ रहा है अब उसे जीत का एक तमगा सा लग चुका है। परिस्थितियों से लोहा लेकर जब शुरुआत की थी तों कचरों का पहाड़ खड़ा था चुनौतियां ज्यादा थी संसाधन कम थे। आज सब कुछ है बस सफ़ाई की अष्टसिद्धि के लिए लगातार ज्यादा परिक्षम कर के फिर एक बार नम्बर वन पर इन्दौर को आना ही होगा। निरंतर हर साल लगातार सेंवन स्टारों के साथ शहर इन्दौर ने स्वछता के सात सितारे लगा कर पूरे भारत के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है । आज नगर निगम इन्दौर महानगर के सफ़ाई मित्र महिला पुरुष दोनों एक निडर व जांबाज सिपाहीयों के भांति ही दिन रात हर समय अपने शहर को चकाचक करने में लगे रहते हैं। इसी मेहनत का फल लगातार सात बार स्वछता का प्रथम पुरस्कार इन्दौर शहर को मिल रहा है। चाहे होली हो दीपावली ईद या गुरुनानक देव का प्रकाश पर्व और महावीर जयंती का परम्परागत जुलूस सभी के पूरे होने के बाद जिस प्रकार शहर के उन जगहों पर जहां यह आयोजन हुएं वहां त्वरित सफ़ाई मिशन शुरू कर फिर से अपने इन्दौर को साफ कर देते हैं। भारत में यह एक अजूबा ही हो रहा है अब पूरे भारत में साफ सफाई व स्वछता एक आंदोलन बन गया है। उस आंदोलन या मिशन का सिरमौर इन्दौर बना हुआ है जो सही राह दिखा रहा। लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन करना इस महायज्ञ में सफाई की इस अष्टसिद्धि के लिए फिर से शहर के नागरिकों समाजिक कार्यकर्ता समाजसेवी संगठन व अन्य धार्मिक संस्थाएं के सदस्य नेता राजनेता जनप्रतिनिधिगण संत महात्मा अधिकारी महापौर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सभी मिलकर इस स्वछता की तपोभूमि इन्दौर में तपस्यारत है और अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। वहीं सफ़ाई मित्र भी अपने शहर को जीतने के लिए आगे बढ़ रहें हैं। यह अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाने की पहल से ही आज कचरे से कंचन तक की यह यात्रा जारी है। यह यात्रा इतनी आसान

नहीं थी कचरों के बड़े बड़े पहाड़ों को हटाने वाला शहर इन्दौर अब भी घमंड लालच से दूर जीत के लिए श्रम साधना का शंखनाद करने के लिए तैयार है। नगर निगम की पूरी टीम साल भर अपने अपने स्तर पर महानगर को सफ़ाई के प्रति जागरूकता व नागरिकों समझता रहेता है वह अति उत्साह में कमियों व नाकारात्मक पहलू से दूर नहीं भागता है इसीलिए हर एक पहेलू पर वैचारिक मंथन व चिंतन कर के इस आठवीं सिध्दी को पाने हेतु प्रयासरत हैं। इस सभी कामों में सफ़ाई मित्र सबसे ज्यादा काम करते हैं इस कर्मवीर कर्मचारियों की सहारना पूरा शहर करता है यह दिन रात का परिश्रम ही है जो बहार से आने वाले लोगों को भी दिखाई देता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के भारत में सफ़ाई स्वछता की जो बातें कही गई थी और जो लोग सुनते भी है की स्वच्छता में ईश्वर का बास होता है उसी बात को जब लालकिले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर के दिन से स्वछता की साधना की बात रखी थी तभी से साफ सफाई का महात्व को हमारा पूरा भारत मान भी रहा है और समझ भी गया है। तभी तो आठ सालों से मध्यप्रदेश के बहुत से शहर इस हवन-यज्ञ में अपनी अपनी आहुति देते आ रहे हैं। खासकर इन्दौर तो इस यंत्र का महामंडलेश्वर प्रथम स्वामी बन गया है। हमारे इन्दौर को मालूम है की कोई भी सिध्दी आसानी से नहीं मिलती इसके लिए साधना करना पढ़ती है क्यों तप तप कर ही सोना बनता है। जमीनी हकीकत से रूबरू होकर हर एक कर्मवीर शहर हितों में सफाई की इस महापूजा या यज्ञ में साधना कर रहे हैं ऐसे सभी साधक को नमन। इसी के बल पर एक बार इन्दौर सिरमौर बनाने में अव्वल हो सकता है टीम भावना व मिलकर कार्यसिद्धि के इस अटूट प्रयास में हर एक गली मोहल्ले हर एक क्षेत्र में हम सभी सफ़ाई मित्रों के साथ अपने शहर के नागरिक होने की जिम्मेदारी निभायें। घर आफिस दफ्तर दुकानों से निकले वाले कचरे को अलग-अलग रख कर गीला सुखा अलग कर के दे और रोको टोको भी जारी रखें यदि कोई कचरा फैला रहा हो गंदगी कर रहा हो तो उसे सही गलत बतायें यह सहयोग ही हमें आगे सफलता दिलाने में मददगार साबित होगा। युवा पीढ़ी को बच्चों को साफ सफाई के बारे में जागरूक करना हमारी जवाबदारी है गंदगी से बिमारियों का सम्राज्य पनपता है। भविष्य में सफाई से ही स्वछता का सिरमौर बनाने में हर एक शहर राज्य आगे बढ़ेंगे , इसलिए इस सफ़ाई की अच्छी शुरुआत को प्रेरणा मानकर जब इन्दौर शहर प्रथम आने के लिए आठवीं बार फिर जीत के लिए आगे बढ़ रहा है तो अन्य राज्यों व शहरों को भी आगे आना होगा। सिर्फ नगर परिषद , नगर निगम के भरोसे या गंदगी फैली हो या सफाई में लापरवाही जनता की हो या निगम की उसे छुपना नहीं चहिए सकारात्मक प्रयासों से एकजुटता से आपस में मिलकर हम यह वचन ले की हम शहर की जागरूकता के सफ़ाई मिशन के लिए अपना नागरिक होने का फ़र्ज़ निभायगे । क्यों बिना मेहनत के साधना कैसे सफल होगी , इसलिए हमारे इन्दौर को अष्टसिद्धि की प्राप्ति के लिए अभी बहुत परिश्रम करना होगा। इन्दौर की दिवारो पर सनातन संस्कृति देशभक्ति के रंग के साथ साथ प्रकृति के करीब लाने हेतु 3 डी कलर में शहर की दीवारों पर तस्वीरें सभी को लुभाती है। और जो चीजें काम नहीं आती है और वह कचरें में अटाले में पड़ी थी उसी बेस्ट चीजों से कबडे से सफ़ाई दीदी और बब्बर शेर घोड़ा आदि बहुत सी कलाकृतियां बनाईं गई जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। छोटी छोटी गलियों से कचरा उठाने के लिए इलेक्ट्रीक रिक्शा छोटी गाड़ी भी घर घर जायेगी। तभी तो इन्दौर को स्वछता की प्रतिस्पर्धा में जीत के लिए अब कठोर साधना की जरूरत है।

डायबिटीज एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है।

डायबिटीज से पीड़ित कई लोगों में उच्च रक्तचाप की समस्या होती है। इससे भी आपके गुर्दे को नुकसान हो सकता है। तंत्रिका सम्बंधी समस्याएँ (डायबिटीज न्यूरोपैथी), जो तंत्रिकाओं और छोटी रक्त वाहिकाओं को क्षति पहुँचने के कारण होती हैं, जो आपकी तंत्रिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती हैं। डायबिटीज एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा है। टाइप १ डायबिटीज, सबसे आम प्रकार है, जिसे काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। वर्तमान साक्ष्य संकेत देते हैं कि दुनिया भर में डायबिटीज का प्रचलन बढ़ रहा है, मुख्य रूप से कई कारकों के कारण मोटापे में वृद्धि के कारण। टाइप १ डायबिटीज को रोकना और नियंत्रित करना एक सतत चुनौती बनी हुई है।

-डॉ० सत्यवान सौरभ

डायबिटीज वैश्विक स्तर पर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरा है और भारत अब व्यापकता और निदान न किए गए मामलों दोनों में सबसे आगे है, जिसमें ३१२ मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और ३० वर्ष से अधिक आयु के १३३ मिलियन लोग उपचार के बिना रह रहे हैं। जीवनशैली में बदलाव, आहार पैटर्न और तंबाकू के उपयोग से प्रेरित भारत में डायबिटीज के मामलों में वृद्धि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के २०३० के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण बाधाएँ खड़ी करती है, यह सुनिश्चित करना कि डायबिटीज से पीड़ित ८०% लोगों का निदान हो और उनमें से ८०% ग्लाइसेमिक नियंत्रण प्राप्त करें। डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब आपका रक्त शर्करा (ग्लूकोज) बहुत अधिक होता है। यह तब विकसित होता है जब आपका अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता है या बिल्कुल भी नहीं बनाता है, या जब आपका शरीर इंसुलिन के प्रभावों पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करता है। डायबिटीज सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है। डायबिटीज के अधिकांश रूप जीर्ण (जीवन भर चलने वाले) होते हैं और सभी रूपों को दवाओं और / या जीवनशैली में बदलाव के साथ प्रबंधित किया जा सकता है। ग्लूकोज (चीनी) मुख्य रूप से आपके भोजन और पेय पदार्थों में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से आता है। यह आपके शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपका रक्त ऊर्जा के लिए उपयोग किए जाने वाले ग्लूकोज को आपके शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचाता है।

जब ग्लूकोज आपके रक्तप्रवाह में होता है, तो उसे अपने अंतिम गंतव्य तक पहुँचने के लिए मदद की ज़रूरत होती है-एक "कुंजी" -यह कुंजी इंसुलिन (एक हार्मोन) है। यदि आपका अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना रहा है या आपका शरीर इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहा है, तो आपके रक्तप्रवाह में ग्लूकोज जमा हो जाता है, जिससे उच्च रक्त शर्करा (हाइपरग्लाइसेमिया) होता है। समय के साथ, लगातार उच्च रक्त शर्करा स्तर के कारण स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं, जैसे हृदय रोग, तंत्रिका क्षति और आंखों की समस्याएँ। डायबिटीज का तकनीकी नाम डायबिटीज मेलिटस है। एक अन्य स्थिति "डायबिटीज" शब्द साझा करती है-डायबिटीज इन्सिपिडस-लेकिन वे अलग-अलग हैं। वे "डायबिटीज" नाम साझा करते हैं क्योंकि वे दोनों अधिक प्यास और बार-बार पेशाब का कारण बनते हैं। डायबिटीज इन्सिपिडस डायबिटीज मेलिटस की तुलना में बहुत दुर्लभ है।

हाल ही में किए गए अध्ययनों में उपवास प्लाज्मा ग्लूकोज के स्तर को शामिल करते हुए डायबिटीज के प्रसार का अधिक व्यापक मूल्यांकन प्रदान किया गया है। यह विशेष रूप से दक्षिण एशिया जैसे उच्च बोझ वाले क्षेत्रों में निदान न किए गए मामलों की पहचान करने में मदद करता है। कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पहल का उद्देश्य नि:शुल्क जांच और प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करना है। निदान तक पहुँच का विस्तार करने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का उपयोग किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन सेवाएँ और मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ कम सेवा वाले क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए तेजी से तैनात की जा रही हैं। डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफ़ॉर्म का एकीकरण रोगी ट्रैकिंग और फ़ॉलो-अप का समर्थन करता है। राष्ट्रीय अभियान डायबिटीज के जोखिम कारकों को कम करने के लिए स्वस्थ आहार और शारीरिक गतिविधि जैसे जीवनशैली में बदलावों को उजागर करते हैं। ३० वर्ष से अधिक आयु के १३३ मिलियन लोगों में निदान नहीं होने के कारण, प्रारंभिक पहचान में एक महत्वपूर्ण अंतर है।

कई व्यक्ति अपनी स्थिति के बारे में लक्षणहीन या अनजान रहते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और कम सेवा वाले क्षेत्रों में। कार्बोहाइड्रेट और संतृप्त वसा से भरपूर अस्वास्थ्यकर आहार, गतिहीन जीवन शैली और डायबिटीज के जोखिम कारक के रूप में तम्बाकू के उपयोग पर अपर्याप्त सार्वजनिक ध्यान समस्या को बढ़ाता है। तम्बाकू के उपयोग से डायबिटीज का ख़तरा ३०-४०% बढ़ जाता है, फिर भी सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों में डायबिटीज से इसके सम्बंध को कम महत्व दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दैनंदिन सुविधाओं और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की महत्वपूर्ण कमी है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में गर्भावधि डायबिटीज प्रबंधन का खराब एकीकरण माताओं और बच्चों के लिए दीर्घकालिक जोखिम को बढ़ाता है। डायबिटीज देखभाल के लिए उच्च आउट-ऑफ-पॉकेट ख़र्च कई व्यक्तियों को समय पर निदान और उपचार लेने से रोकता है। समन्वित कार्यवाही का अभाव: निदान सेवाओं, उपचार सुविधाओं और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के बीच कमज़ोर सम्बंध व्यापक डायबिटीज प्रबंधन में बाधा डालते हैं।

डायबिटीज का निदान होना जीवन बदलने वाली घटना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। डायबिटीज का प्रबंधन करने के लिए निरंतर देखभाल और परिश्रम की आवश्यकता होती है। हालाँकि यह शुरू में बहुत भारी लग सकता है, लेकिन समय के साथ आप इस स्थिति का प्रबंधन करने और अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाने में बेहतर समझ हासिल कर लेंगे। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (ओं) से नियमित रूप से मिलते रहें। डायबिटीज के प्रबंधन में टीम के प्रयास की आवश्यकता होती है-आप चाहेंगे कि चिकित्सा पेशेवर, मित्र और परिवार आपके साथ हों। यदि आपको मदद की आवश्यकता हो तो उनसे संपर्क करने में संकोच न करें। जबकि भारत ने डायबिटीज को सम्बोधित करने के लिए कदम उठाए हैं, चुनौती की गंभीरता को देखते हुए गहन और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। निदान को बढ़ाना, प्राथमिक स्तर पर व्यापक देखभाल को एकीकृत करना और जीवनशैली और व्यवहार सम्बंधी कारकों, विशेष रूप से तंबाकू के उपयोग को सम्बोधित करना, २०३० के डब्ल्यूएचओ लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

रो रहा संविधान।।

संसद में मचता गदर, है चिंतन की बात।
हँसी उड़े संविधान की, जनता पर आघात।।

भाषा पर संयम नहीं, मर्यादा से दूर।
संविधान को कर रहे, सांसद चकनाचूर।।

दागी संसद में घुसे, करते रोज मखौल।
देश लुटे लुटता रहे, खूब पीटते ढोल।।

जन जीवन बेहाल है, संसद में बस शोर।
हित सौरभ बस सोचते, सांसद अपनी ओर।।

संसद में श्रीमान जब, कलुषित हो परिवेश।
कैसे सौरभ सोचिए, बच पायेगा देश।।

लोकतंत्र अब रो रहा, देख बुरे हालात।
संसद में चलने लगे, थप्पड़, घूसे, लात।।

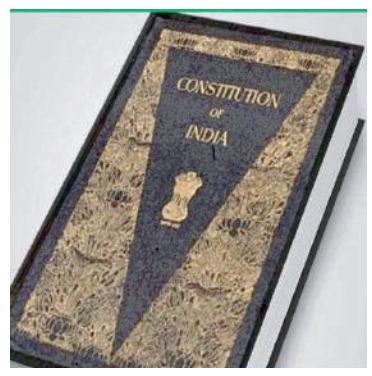

जनता की आवाज का, जिन्हें नहीं संज्ञान।
प्रजातंत्र का मंत्र है, उन्हें नहीं मतदान।।

हमें आज है सोचना, दूर करे ये कीच।
अपराधी नेता नहीं, पहुंचे संसद बीच।।

अपराधी सब छूटते, तोड़े सभी विधान।
निर्दोषी है जेल में, रो रहा संविधान।।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप को हराने की साजिश, वोटर लिस्ट में हेर-फेर कर रही केंद्र; मुख्यमंत्री आतिशी का गंभीर आरोप

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि वह दिल्ली में अधिकारियों पर दबाव बनाकर आम आदमी पार्टी के वोट कटवा रही है। उन्होंने कहा कि एक डीएम ने अपने अंतर्गत आने वाले सात सहायक चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के 20000 वोट काटने हैं। इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए क्लिक करें।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में केंद्र सरकार अधिकारियों पर दबाव बनाकर आम आदमी पार्टी (AAP) के वोट कटवा रही है। उन्होंने बगैर नाम लिए प्रेस वार्ता में कहा कि एक डीएम ने अपने अंतर्गत आने वाले सात सहायक चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उन्हें आम आदमी पार्टी के 20000 वोट काटने हैं।

इन सहायक चुनाव अधिकारियों ने बूथ लेवल अधिकारियों को बुलाकर इस बारे में निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि एक एसडीएम ने ही अपने यहां के बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक बुलाकर आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए कहा है।

इलाके में वोट नहीं बनाने का दिया आदेश

इसके साथ यह भी कहा है कि उनके इलाके में कोई नया वोट नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा दिल्ली में चुनाव नहीं जीत पा रही है। अब उसने केंद्र सरकार को एक लिस्ट दी है, जिसके तहत केंद्र सरकार अधिकारियों पर दबाव बनाकर आम आदमी पार्टी के वोट कटवा रही है।

AAP को हराने के लिए बड़ी साजिश

आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को हराने की यह एक बड़ी साजिश है और इसी के तहत गत 28 अक्टूबर को 29 एसडीएम और एडीएम को बदला गया है।

किराए के कमरे में 500 के नोटों की छपाई, 17 लाख के जाली नोट बरामद; दिल्ली पुलिस ने पकड़े चार 'फर्जी'

दिल्ली पुलिस ने पांच सौ रुपये के जाली नोट छापने और सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बाहरी उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ ने लगभग 17 लाख रुपये की जाली नोट बरामद किए हैं और चार लोगों को गिरफ्तार किया है। एक शख्स को गाजियाबाद के खोड़ा से गिरफ्तार किया है। नोट छपाई का काम खोड़ा कॉलोनी में किया जाता था।

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पांच सौ रुपये के जाली नोट छापने और सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बाहरी उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ ने लगभग 17 लाख रुपये की जाली नोट बरामद किए हैं और चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

एक शख्स को गाजियाबाद के खोड़ा से गिरफ्तार किया है। नोट छपाई का काम खोड़ा कॉलोनी में किया जाता था। तीन लोग जाली नोट सप्लाई का काम देखते थे और एक छपाई करता था। सप्लाई करने वाले तीन आरोपियों को अलग-अलग समय में अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया है।

बाहरी उत्तरी जिला उपायुक्त निधिन वल्सन ने बताया कि पुलिस ने इस गिरोह से कुल 919 पांच सौ रुपये के नोट, साथ ही 621 ए4 आकार की जाली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) शीट (कुल कीमत 17,01,500), एक लैपटॉप, एक रंगीन प्रिंटर, दो लेमिनेटर, एक पेपर कटिंग मशीन, ए4 आकार के कागज के नौ बंडल, वॉटरमार्क बनाने के लिए एक गांधी की मोहर, कुछ पेपर कटर, एक पेपर प्रेसिंग मशीन और जाली मुद्रा छापने में इस्तेमाल होने वाली अन्य वस्तुएं बरामद की हैं।

ये हैं गिरफ्तार आरोपी

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दिल्ली के समयपुर बादली थाना क्षेत्र में खेड़ा खुर्द गांव का विकास भारद्वाज, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के चकरौत गांव (थाना करनैलगंज) का सत्यम सिंह, गोंडा जिले की तहसील तरबगंज के कद्रहन पुरवा गांव निवासी सचिन और उत्तर प्रदेश के बरेली के मीरगंज (सिरौली रोड, राजेंद्र नगर वार्ड-8) निवासी अनुराग शर्मा शामिल है।

किराए के कमरे में होती थी छपाई

उन्होंने बताया कि सचिन (22) खोड़ा कॉलोनी में किराए के कमरे में जाली नोट छापता था और अन्य तीनों सप्लाई करते थे। जाली नोट का मुख्य आपूर्ति करने वाला खेड़ा खुर्द गांव निवासी विकास भारद्वाज है।

प्रदूषण: न खत्म होने वाला सच

प्रदूषण, हमारे समय का सबसे बड़ा और खतरनाक सच है। यह समस्या न केवल हमारे पर्यावरण को बर्बाद कर रही है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गंभीर खतरा भी पैदा कर रही है। दुर्भाग्यवश, हमारे समाज और देश ने इस मुद्दे को कभी गंभीरता से नहीं लिया। चुनावी वादों में मुफ्त बिजली और पानी की गूंज सुनाई देती है, लेकिन पर्यावरण और प्रदूषण जैसे मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं।

जब हम प्रदूषण के विषय में सोचते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या हम इसे हल करने के लिए सच में प्रयास कर रहे हैं, या बस इसे नजरअंदाज कर रहे हैं? आज हर दिशा में प्रदूषण ने अपनी जड़ें फैला ली हैं, चाहे वह वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, या अन्य किसी रूप में। यह केवल एक पर्यावरणीय संकट नहीं है, बल्कि हमारी खुद की बनाई हुई समस्याओं का आईना है।

प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है चाहे वो सांस लेने की शुद्ध हवा हो, पीने का साफ पानी हो, और एक सुंदर पर्यावरण। लेकिन आज विकास की होड़ में हमने इस धरती पर ऐसे घाव दिए हैं जिनकी भरपाई शायद संभव नहीं दिखाई पड़ती है। सवाल उठता है, क्या यह वही विकास है जो हमें चाहिए था? क्या यह उन्नति है या विनाश?

विकास या विनाश?

विकास की योजनाओं में सरकार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लेकिन क्या हमारे नीति-निर्माता पर्यावरण और मानव जीवन के संतुलन को प्राथमिकता दे रहे हैं? शायद नहीं। सड़कें चौड़ी करने के नाम पर हिमालय की छाती को काटा जा रहा है। पेड़ पौधे जो हमारी धरती का फेफड़ा है उसे उजाड़ कर कंक्रीट का जंगल खड़ा किया जा रहा है। ये वही हिमालय है जो न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व की जलवायु का संतुलन बनाए रखता है।

सरकार के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जैसे चार धाम सड़क परियोजना, पर्यटकों के लिए लग्जरी सुविधाएं, हेलीपैड निर्माण और तमाम वीआइपी सुविधा ये सब कहीं न कहीं इस प्राकृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और पहाड़ों को काटने का सीधा असर ग्लेशियरों के पिघलने और भूस्खलन की घटनाओं में बढ़ोतरी के रूप आए दिन सामने आता है।

मसलन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी है कि क्या विकास का यह मॉडल टिकाऊ है? यदि पर्यावरण नष्ट होगा, तो पर्यटन या सुविधाएं किसके लिए रहेंगी?

मुख्य कारण पर्यावरण के विनाश का

फैक्ट्रियां और उद्योग, जो हमारे विकास का आधार माने जाते हैं, पर्यावरण के सबसे बड़े शत्रु हैं।औद्योगीकरण ने हमें रोजगार और विकास के साधन दिए हैं, लेकिन इसकी कीमत पर्यावरण ने चुकाई है। कई उद्योग पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं करते और जहरीले कचरे को सीधे नदियों में बहा देते हैं। गंगा और यमुना जैसी नदियां, जो हमारी आस्था और जीवन का प्रतीक हैं, आज प्रदूषण से कराह रही हैं।

सरकार की क्लीन गंगा मिशन जैसी योजनाएं कागजों तक सीमित हैं। हर एक सरकार ने अपनी सहूलियत के अनुसार गंगा, यमुना जैसे तमाम नदियां को सफाई करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। बजट आवंटित होता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इसका असर दिखाई नहीं देता। " हमारी सरकार आएगी तो गंगा मैं आपको तैरती हुई मछली दिखाई देगी, इतना साफ कर दूंगा " यहां से ले कर " हमारी सरकार आएगी तो यमुना के पानी को पीने योग्य बना देंगे" जैसे अनगिनत सरकार के वादों को सुनते सुनते टैक्स देने वाली जनता के न जाने कितने लाख करोड़ यमुना और गंगा मैं विसर्जन हो गए, ये सब पैसे बंगाल की खड़ी मैं समाहित हो गया होंगे। लेकिन गंगा - यमुना बद से बत्तर होती जा रही है। यह स्पष्ट है कि पर्यावरणीय मुद्दों को प्राथमिकता देने के बजाय सरकार कॉर्पोरेट मुनाफे को तरजीह दे रही है।

भारत में निजी वाहनों की संख्या प्रतिदिन आसमान छू रही है, और इसके साथ ही प्रदूषण का स्तर भी। बड़े शहरों में जहरीली हवा का स्तर खतरनाक सीमा को पार कर चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास धीमे हैं, और सार्वजनिक परिवहन का विकास भी पर्याप्त नहीं है।

इस समस्या को हल करने के लिए सख्त नीतियों और प्रभावी इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सरकार को निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि सस्ती और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन सेवाएं उपलब्ध हों, तो लोग निजी वाहनों का उपयोग कम करेंगे, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी।

हमारे त्योहार, जो कभी प्रकृति और समाज के बीच सामंजस्य का प्रतीक होते थे, आज दिखावे और पर्यावरण विनाश का पर्याय बन गए हैं। दिवाली पर पटाखों का शोर, शादी-ब्याह में पटाखों की अंधाधुंध प्रदर्शन, और इनसे होने वाला वायु और ध्वनि प्रदूषण हमारे समाज की मानसिकता को दर्शाता है।

इससे न केवल इंसान परेशान है पशु पक्षी भी इस प्रदूषण के चपेट से अछूते नहीं है।

कई लोग यह तर्क देते हैं कि पटाखे जलाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन क्या यह संस्कृति उस वक्त थी जब पर्यावरण इतना संकटग्रस्त नहीं था?

श्रीराम जब अयोध्या लौटे थे, तो उनके स्वागत में सिर्फ दीये जलाए गए थे।

उनका स्वागत किसी पटाखे से नहीं हुआ था। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा धर्म और परंपराएं प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देती हैं, न कि उसे नुकसान पहुंचाने का।

यहां तक कि धार्मिक स्थल भी इस प्रदूषण की चपेट में हैं। हर साल हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य से मिलने के लिए पहाड़ों और नदियों की ओर जाते हैं, लेकिन पीछे छोड़ जाते हैं प्लास्टिक कचरे और जल स्रोतों को प्रदूषित करने वाली गंदगी। यह हमारी आस्था के नाम पर प्रकृति को पहुंचाई जा रही चोट है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

पर्यटकों को सुविधाएं देने के नाम पर लग्जरी होटल, फाइव-स्टार वॉशरूम और प्लास्टिक के कचरे का अंबार हमें इस हद तक ले आया है कि हम अपने ही पर्यावरण को खो रहे हैं। क्या हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि जो पर्यावरण हमें जीवन देता है, उसके बिना हमारा भविष्य अधूरा है?

देश में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। सड़क निर्माण, ऊंची इमारतों का निर्माण और मेट्रो परियोजनाओं ने धूल प्रदूषण को बढ़ा दिया है। 24 घंटे चलने वाले इन कार्यों से हवा में कणों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है।

ध्वनि प्रदूषण भी एक बड़ा मुद्दा है। निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली भारी मशीनें और औजार शोर मचाते हैं, जिससे आस-पास रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं।

प्रदूषण की इस भयावह कहानी में एक और पहलू है हमारे गांवों का। लकड़ी और कोयले का उपयोग, जो अभी भी कई जगहों पर आम है, घरों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहा है। महिलाएं और बच्चे, जो इन चूल्हों के धुएं में दिनभर रहते हैं, सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं।

सरकार ने उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं शुरू कीं, लेकिन उनका लाभ सीमित रहा। क्या सरकार ने सोचा कि सिलेंडर महंगे होने पर लोग फिर से लकड़ी और कोयले की ओर लौट जाएंगे?

भारत के महानगरों में ट्रैफिक जाम आम समस्या बन चुकी है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे शहरों में गाड़ियां घंटों तक जाम में फंसी रहती हैं। इससे फालतू ईंधन जलता है और वायु प्रदूषण का स्तर और खतरनाक हो जाता है।

वाहनों का लंबे समय तक चालू रहना और धीमी गति से चलना पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इससे न केवल ईंधन की बर्बादी होती है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था पर भी दबाव डालता है।

पर्यावरण की ओर सकारत्मक कदमः यही समय है, सही समय है

रवींद्रनाथ टैगोर के कहा था कि "प्रकृति से छेड़छाड़ करना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है।"

आइए मिल के पर्यावरण बदलते है। बदलाव खुद से शुरू करते है।

प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार और समाज दोनों को साथ आना होगा। हमें सरकार से मांग करनी होगी कि वह पर्यावरणीय नीतियों को सख्ती से लागू करे। औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, सार्वजनिक परिवहन का सशक्तिकरण, और हरित ऊर्जा को प्राथमिकता देना जरूरी है।

वहीं, समाज के स्तर पर हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। त्योहारों को प्रदूषण मुक्त तरीके से मनाना, प्लास्टिक का उपयोग कम करना, और ऊर्जा संरक्षण के तरीकों को अपनाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

प्रदूषण की सबसे भयावह सच्चाई यह है कि यह सरहदों को नहीं मानता। दिल्ली का वायु प्रदूषण हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश तक पहुंचता है। यही नहीं, यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को भी पार कर जाता है और दूसरे देशों को प्रभावित करता है।

फ्लड हो या वायु प्रदूषण, इसे इस बात की परवाह नहीं कि इसका शिकार कौन होगा। इसका असर सब पर समान रूप से पड़ता है। हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण जाति, धर्म, मजहब या सरहदों से बंधा नहीं है। यह सभी को समान रूप से प्रभावित करता है।

हमारे धर्मगुरुओं, समाज सुधारकों और नेताओं को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। समाज में सुधार लाने के लिए राजा राममोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों की आवश्यकता है।

जैसे सोनम वांगचुक पर्यावरण को केंद्र में रखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, वैसे ही अन्य समाज सुधारकों को भी इस मुहिम में शामिल होना चाहिए।

प्रदूषण न केवल एक समस्या है, बल्कि यह हमारी असंवेदनशीलता का प्रतीक भी है। हमें व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव लाना होगा। छोटे कदम, जैसे वाहन का कम उपयोग, प्लास्टिक का परहेज, और पेड़ लगाना, इस लड़ाई में बड़ा योगदान दे सकते हैं।

हमारे पास अभी भी समय है। आइए, मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को शुद्ध हवा और पानी मिले। क्योंकि अंततः, हमें इसी धरती पर रहना है, इसी हवा में सांस लेनी है। प्रदूषण केवल एक समस्या नहीं है, यह हमारी असंवेदनशीलता का प्रतीक भी है। हमें यह समझना होगा कि पर्यावरण बचाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अभी भी समय है। हमें अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना होगा। यह न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारा कर्तव्य भी है।

- आशीष कुमार

अरविंद केजरीवाल से मिले हेमंत सोरेन, शपथ ग्रहण समारोह का दिया न्योता

झारखंड में चुनाव जीतने के बाद हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। यह मुलाकात केजरीवाल के घर पर हुई। इस दौरान सोरेन ने आप चीफ को 28 नवंबर को होने वाले मुख्यमंत्री पद की शपथ में शामिल होने का न्योता दिया। वहीं दिल्ली में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

नई दिल्ली। हेमंत सोरेन मंगलवार को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। चुनाव में जीत के बाद हेमंत सोरेन आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर आए।

इस दौरान हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण समारोह के लिए अरविंद केजरीवाल को न्योता भी दिया। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

बता दें कि हाल में झारखंड में हुए चुनाव में हेमंत सोरेन की पार्टी ने जीत हासिल की है। अब हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे।

28 नवंबर को शपथ लेंगे हेमंत सोरेन

बता दें कि हेमंत सोरेन 28 नवंबर को राजधानी के मोरहाबादी मैदान में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। खास बात यह है कि हेमंत अकेले ऐसे नेता बन जाएंगे जो राज्य की चौथी बार सीएम पद की शपथ लेंगे।

सामान्य तौर पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन में करने की परंपरा है, लेकिन इस बार सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की जीत बड़ी है और समर्थकों के साथ-साथ कैडरों का उत्साह भी बढ़ाने वाली है। यही कारण है कि इस मौके को खास बनाने की पूरी तैयारी की जा रही है।

उपराज्यपाल ने नशे के खिलाफ छेड़ी जंग, तीन साल में राजधानी को नशा मुक्त करने का करने का लक्ष्य

दिल्ली में नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने एक महीने के नशा विरोधी अभियान की घोषणा की है। यह अभियान 1 दिसंबर से शुरू होगा और इसका उद्देश्य दिल्ली को अगले तीन वर्षों में नशा मुक्त बनाना है। अभियान में बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा जिसमें स्कूलों कॉलेजों होस्टलों दवा की दुकानों पान की दुकानों आदि अन्य सार्वजनिक स्थानों की गहन जांच शामिल है।

नई दिल्ली। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लगातार बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली में माह भर के लिए नशा विरोधी अभियान चलाने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत एक दिसंबर से होगी। एलजी की यह पहल अगले तीन वर्षों में दिल्ली को नशा मुक्त बनाने की बड़ी योजना का हिस्सा है। सक्सेना ने, राज्य स्तरीय समिति नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की नौवीं समीक्षा बैठक के दौरान इस बात को रेखांकित किया कि इसका एक सामाजिक पहलू युवाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता प्रतिकूल प्रभाव है। साथ ही व्यापक अंतरराष्ट्रीय पहलू भी है।

नशीली दवाओं का उपयोग रणनीतिक रूप से भारत के युवाओं और देश को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर, मादक पदार्थों की तस्करी और खपत पर अंकुश लगाने के अपने प्रयासों को तेज करने का निर्देश दिया। अभियान में बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल होंगे। एलजी ने दिल्ली पुलिस और दूसरी सभी संबंधित एजेंसियों को इस एक महीने के अभियान के दौरान लगभग 200 होस्टलों, 50 कालेजों, 200 स्कूलों, 200 दवाओं की दुकानों, 500 पान की दुकानों, सभी शेल्टर होम्स, 200 बार और रेस्तरां, सभी रेलवे स्टेशनों, सभी आईएसबीटी और दूसरे सार्वजनिक स्थलों की गहनता से जांच करने और उन्हें साफ-सुथरा रखने का भी निर्देश दिया है।

इसके अलावा कैंपस में नशा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे और शैक्षणिक संस्थानों में होस्टल को नशा मुक्त सुनिश्चित करने के लिए वार्डन को जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को भी इसमें शामिल कर शिक्षकों और अभिभावकों को एडवाइजरी भेजने के निर्देश दिए हैं। समाज कल्याण विभाग स्कूलों और अभिभावकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़कर उन्हें नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में शिक्षित करेगा और उन्हें अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

सक्सेना ने दिल्ली पुलिस से मुखबिरों की पहचान को गोपनीय रखते हुए व्यापक रूप से जागरूक करने और उनके लिए आकर्षक पुरस्कारों की घोषणा करने को कहा है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नशीली दवाओं और नशीले पदार्थों के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के खिलाफ पूरी दिल्ली में, डीटीसी बसों में, आटो-रिक्शा और टैक्सियों पर नारे, पोस्टर और बैनर को प्रमुखता से लगाया जाएगा। दिल्ली को नशा मुक्त बनाने के लिए टेलीविजन, रेडियो, सोशल मीडिया और आउटडोर विज्ञापन सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू किए जाएंगे। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए शहर भर में और डीटीसी बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों में नारे, पोस्टर और बैनर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे।

चाइल्ड पी.जी.आई में नर्सिंग स्टाफ का हल्लाबोल, अपनी मांग लिए धरना-प्रदर्शन पर बैठे

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा के सेक्टर-30 स्थित चाइल्ड पीजीआई में अनुबंध पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर मंगलवार सुबह मुख्य गेट के पास धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्टाफ का आरोप है कि प्रबंधन ने छह साल से नियमानुसार वेतन नहीं बढ़ाया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट और प्रबंधन के अन्य अधिकारियों से वार्ता विफल होने के बाद भी धरना जारी है।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा। सेक्टर-30 स्थित चाइल्ड पीजीआई में आउटसोर्स नर्सिंग स्टाफ ने मंगलवार सुबह वेतन बढ़ोतरी की मांग पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। 50 सदस्यों ने दोपहर ढाई बजे तक मुख्यगेट के पास जमकर नारेबाजी की। आरोप है कि एजेंसी और प्रबंधन ने छह साल से वेतन नहीं बढ़ाया है।

सूचना पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट और फैसेलिटी मैनेजर प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने पहुंचे। दोनों पक्षों की बातचीत विफल रही। बुद्धवार को भी विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी अनुकेंद्र शर्मा ने बताया कि छह साल पहले आउटसोर्सिंग पर 120 से ज्यादा लोगों को अनुबंध पर तैनाती की गई थी, जिसमें प्रबंधन को पांच प्रतिशत वेतन बढ़ाना था।

2020 में ग्रेड-2 आउटसोर्स कर्मचारियों का बढ़ा वेतन

मगर वेतन नहीं बढ़ा। सभी कई महीनो से वेतन बढ़ाने के लिए ज्ञापन दे चुके हैं। 21 नवंबर को भी चाइल्ड पीजीआई के निदेशक के नाम डाक से एक पत्र भेजा था। उसमें 100 से ज्यादा स्टाफ ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें 2018 से वेतन नहीं बढ़ने की बात रखी थी जबकि 2020 में ग्रेड-2 आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ाकर दिया। आरोप है कि स्टाफ से मेडिकल खर्चा, आवासीय किराया लेते हैं।

ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया और महिला स्टाफ को मेटरनिटी छुट्टी लेने पर दोबारा नौकरी पर नहीं लिया जाता। इन आरोपों के साथ स्टाफ ने नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। दोपहर दो बजे प्रदर्शनकारी डटे रहे। बुद्धवार को भी विरोध जारी रहेगा।

हम लोगों की छह साल से सैलरी नहीं बढ़ी है। निदेशक और एजेंसी के फैसिलिटी मैनेजर को भी लिखकर दे चुकें हैं लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। मजबूरी में हमें प्रदर्शन करना पड़ा।

यह विरोध मांग पूरी न होते तक जारी रहेगा- **चन्द्रप्रकाश**

स्टाफ नर्स की कोई सुनवाई नहीं हो रही। अधिकांश स्टाफ को ज्वानिंग लेटर नहीं दिया गया। विरोध करने पर हर बार आश्वासन देकर जिम्मेदारी पलड़ा झाड़ लेते हैं।-प्रियंका

प्रदर्शन के दौरान फैसिलिटी मैनेजर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। अनुबंध के बावजूद पांच प्रतिशत वेतन बढ़वाने के लिए हम सभी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।-**जितेंद्र**

एजेंसी ने 2020 में भर्ती किए स्टाफ का वेतन बढ़ा दिया जबकि हमसे अस्पताल में मेडिकल खर्चा, आवासीय किराया लिया जाता है। ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं दिया।- **बृजेश जांगिड**

हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का नहीं मिल रहा लाभ, सालान 60 करोड़ का नुकसान; सांसद ने मंत्री को लिखा पत्र

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद जिले के हिंडन एयरपोर्ट पर हर साल 60 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को उड़ान सेवा का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। यह बात अपने पत्र के माध्यम से जिले के सांसद अतुल गर्ग ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को दी है। जिसमें उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए।

गाजियाबाद। हिंडन एयरपोर्ट पर सालाना 60 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को उड़ान सेवा का पर्याप्त लाभ नहीं मिल रहा है।

इसकी वजह ज्यादातर फ्लाइट का कैंसिल हो जाना है। इसकी वजह से एक तरफ दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ सालना 60 करोड़ रुपये का नुकसान सरकार को हो रहा है।

इन शहरों के लिए भी शुरू हो उड़ान सेवा- अतुल गर्ग

यह जानकारी सांसद अतुल गर्ग ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को एक पत्र के माध्यम से देते हुए उनसे हिंडन एयरपोर्ट से अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और लखनऊ जैसे शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू कराने की मांग की है।

हिंडन एयरपोर्ट से नियमित उड़ान सेवा शुरू कराने को लेकर सांसद अतुल गर्ग लगातार प्रयास कर रहे है। उन्होंने इस संबंध में पूर्व में भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पत्र लिखकर उड़ान सेवा शुरू न होने के संबंध में जानकारी मांगी थी। उन्होंने एयरपोर्ट पर होने वाले सालाना खर्च का ब्यौरा भी मांगा था।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली NCR के लोगों को मिलेगा लाभ

पत्र का जवाब मिलने पर उनको पता चला कि हिंडन एयरपोर्ट से 66 फ्लाइट की उड़ान की मंजूरी है, लेकिन इनमें से अधिकतर फ्लाइट की उड़ान सेवा उड़ान वाले दिन रद कर दी जाती है।

उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू (Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu) को यह जानकारी देते हुए बताया कि हिंडन एयरपोर्ट से प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी जैसे शहरों से उड़ान सेवा शुरू होने पर न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।

जल्द हो समस्या का समाधान-सांसद गर्ग

बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ भी कम होगी। गाजियाबाद समेत आसपास के जिलों के लोग आसानी से हिंडन एयरपोर्ट से उड़ान सेवा का लाभ ले सकेंगे।

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सांसद को आश्वासन दिया है कि जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा।

गाजियाबाद को जनवरी में मिलेगी बड़ी सौगात; प्रदूषण को कम करने में होगी मदद

यूपी के गाजियाबाद जिले के लिए एक गुड न्यूज है। जिले के लोगों को जल्द ही 80 सीएनजी बसें मिलने वाली हैं। इन बसों के संचालन से जिले में प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं इन बसों का संचालन अलग-अलग रूटों के लिए किया जाएगा जिससे यात्रियों को काफी फायदा होगा। आगे विस्तार से पढ़िए पूरा अपडेट।

गाजियाबाद। यूपी के गाजियाबाद जिले के लिए एक अच्छी खबर है। जिले के लोगों को जनवरी तक 80 सीएनजी बसों की सौगात मिल जाएगी। इससे कौशांबी डिपो से विभिन्न शहरों के लिए जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। साथ ही सीएनजी बसों के संचालन से प्रदूषण भी कम होगा। अभी तक यहां बड़ी संख्या में सीएक्यूएम द्वारा प्रतिबंधित पुरानी बसों का संचालन किया जा रहा है।

CNG और ई-बसों में बदला जाना है करीब 500 बसों को

प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एनसीआर के सभी जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल बसों पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। गाजियाबाद रीजन में करीब 500 बसों को सीएनजी और ई-बसों में बदला जाना है।

वायु प्रदूषण को रोकने में मिलेगी मदद

इसके लिए परिवहन निगम के अधिकारी मुख्यालय को कई बार पत्र लिख चुके हैं। मुख्यालय ने कौशांबी डिपो के लिए 80 सीएनजी बसें अलाट कर दी हैं। जिससे इन बसों से वायु प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी।

अगले माह से मिलनी शुरू हो जाएंगी बसें

अधिकारियों का कहना है कि अगले माह से बसें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जनवरी तक सभी बसें मिल जाएंगी। इन बसों के संचालन से यात्रियों को राहत मिलेगी। बसों का ऐसे रूटों पर संचालन किया जाएगा, जहां से यात्री अधिक निकल रहे हैं और जहां बसों की संख्या कम है। साथ ही कई रूटों पर संचालित खटारा बसों के स्थान पर नई बसों का संचालन किया जाएगा। कौशांबी डिपो में अभी 122 सीएनजी बसें हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में भी इन बसों को चलाने की है योजना

ग्रामीण क्षेत्रों को शहर से जोड़ने के लिए मुख्यालय ने बीते वर्ष सर्वे कराया था। जिसमें कौशांबी डिपो से चार रूट निर्धारित किए गए थे। निगम के अधिकारी इन रूटों से भी नई बसें संचालित करने की योजना बना रहे हैं।

यह भी पढ़ें- कानपुर में ढहा 150 साल पुराने ऐतिहासिक गंगापुल का एक हिस्सा, अंग्रेजों के जमाने में हुआ था निर्माण

24 बसें की जाएंगी नीलाम

कौशांबी डिपो की 24 बसों की उम्र पूरी होने वाली है। इन बसों को भी जनवरी तक नीलाम कर दिया जाएगा। डिपो में करीब 36 बसें ऐसी थीं, जिन्हें नीलाम किया जाना है। इनमें से 12 बसों को नीलाम किया जा चुका है। मुख्यालय से बसें अलाट कर दी गईं हैं। दो माह में सभी बसें मिल जाएंगी। इन बसों का संचालन यात्रियों की जरूरत के हिसाब से किया जाएगा।

ग्रेटर नोएडा की फिल्म सिटी को लेकर आया अपडेट, जमीन खरीदने का काम पूरा; जानिए कब से होगा निर्माण

ग्रेटर नोएडा। फिल्म सिटी का लेआउट प्लान दिसंबर अंत तक तैयार हो जाएगा। बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. व यमुना प्राधिकरण के बीच जुलाई में अनुबंध हुआ था। इसके तहत छह माह में लेआउट प्लान स्वीकृति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।

प्राधिकरण विकासकर्ता कंपनी बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. को जल्द ही जमीन का भौतिक कब्जा सौंप देगा। अगले साल से फिल्म सिटी का निर्माण शुरू होने की संभावना है।

तीन साल में फिल्म सिटी होगी विकसित

यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 21 में 230 एकड़ में फिल्म सिटी विकसित करने के लिए बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. (Bayview Bhutani Film City Pvt. Ltd.) के साथ जुलाई में अनुबंध हस्ताक्षर किए थे। फिल्म निर्माण निर्देशक बोनी कपूर की अगुवाई वाली इस कंपनी को तीन साल में फिल्म सिटी विकसित कर फिल्म निर्माण की गतिविधियों को शुरू करना है।

लेकिन यमुना प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र होने के कारण निर्माण कार्य शुरू करने से पहले फिल्म सिटी के लेआउट प्लान की प्राधिकरण से स्वीकृति लेनी अनिवार्य है।

फिल्म सिटी के लिए खरीदी गई जमीन

प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र भाटिया ने बताया कि दिसंबर तक लेआउट प्लान स्वीकृति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इसे मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। फिल्म सिटी के लिए जमीन क्रय करने का कार्य तकरीबन पूरा हो चुका है। जल्द ही विकासकर्ता को कब्जा सौंप दिया जाएगा।

पहले चरण में 230 एकड़ पर होगा निर्माण

फिल्म सिटी परियोजना (Film City Project) एक हजार एकड़ और दस हजार करोड़ की है, लेकिन पहले चरण में 230 एकड़ में इसको विकसित किया जा रहा है। इसे सात जोन में विकसित किया जाएगा। इसमें फिल्म निर्माण के लिए स्टूडियो, ध्वनि व प्रकाश के विशेष प्रभाव वाले स्टूडियो, कमर्शियल कांप्लेक्स, विला, कार्यालय, आउटडोर लोकेशन आदि होंगे।

कंपनी करेगी निर्माण और संचालन

फिल्म सिटी के लिए स्पेशल परपज कंपनी बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्रा. लि. का गठन किया गया है। बोनी कपूर को कंपनी का चेयरमैन बनाया गया है। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी इसमें निदेशक के तौर पर शामिल किए गए हैं। कंपनी को फिल्म सिटी के निर्माण एवं संचालन के लिए 90 साल का लाइसेंस दिया गया है। कंपनी को होने वाली कमाई से 18 प्रतिशत राजस्व प्राधिकरण को मिलेगा।

जीना है तो हंस के जियो एक पल भी परेशान होना ना हौसला कभी टूटे ना धीरज कभी छूटे ना

चुनावी हार जीत होती रहती है, प्रसन्नता मंन की शांति व संतोष भरे मन से जीते व हारे उम्मीदवारों को फिर जनता की सेवा में आगे बढ़ना ज़रूरी

वैश्विक स्तरपर भारत की अनेकों बाणीयाँ, कथन सुविचार सारी दुनियाँ में यानें जग प्रसिद्ध हैं, उनमें एक नानक दुखिया सब संसार बाणी है, हर किसी को कोई ना कोई दुख ज़रूर है, उसके बाद ही फिर सुखों की शुरुआत होती है इसीलिए हर स्थिति हर वेले में प्रसन्नता खुशी संतुष्टि उम्मीद में संभावना जरूर रखनी चाहिए कि दुख आया है तो सुख भी आएगा, हारे हैं तो जीतेंगे भी हर वेले ईश्वर अल्लाह को का शुक्राना अदाकार मौज में मस्त रहे व जनता की सेवा करते रहें, आज इस विषय पर हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 23 नवंबर 2024 को आए महाराष्ट्र झारखंड व अन्य उपचुनावों में सैकड़ो व्यक्ति ही जीते हैं परंतु हजारों व्यक्ति हारें हैं। मैंने रिसर्च कर आंकड़े निकालें, महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए 4136 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े व जिसमें प्रत्याशी हारे। झारखंड में प्रथम द्वितीय चरण मिलकर 81 सीटों के लिए 1377 प्रत्याशी हारे हैं व अनेक राज्यों के उपचुनाव में भी मात्र कुछ सीटों पर सैकड़ो व्यक्ति हारें हैं।23 नवंबर 2024 को आए नतीजे में करीब 390 सीटों पर ही चुनाव जीते तो करीब करीब 6 हज़ार से अधिक प्रत्याशी चुनाव हार गए परंतु हौसला धीरज संतुष्टि रख, हंस के व प्रसन्नता में रहकर अगले चुनाव में जीत के लिए लक्ष्य बनाकर जनता की सेवा में फिर जुट जाना चाहिए। मैं 26 नवंबर 2024 को सुबह 1989 में रिलीज हुई थानेदार हिंदी फीचर फिल्म का गीत जीना है तो, हंस के जियो, जीवन में एक पल भी परेशान होना ना, रोना ना, जिंदगी रो रो के जीवन ये खोना ना। हौसला ज़ज्बा धीरज कभी टूटे ना की तर्ज पर यह गीत सुनकर चुनाव में असफल व्यक्तियों के पक्ष में उनके सहानुभूति में यह आर्टिकल तैयार किया हूं उम्मीद है यह गीत सुनेंगे यह आर्टिकल पढ़कर हौसला अफजाई व धीरज रखकर आगे बढ़ेंगे।चूँकि उम्मीद व हौसला अफ़जाई कर आज हारें हैं, कल जीतेंगे, मेहनत करेंगे इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे चुनावी हार जीत होते रहती है प्रसन्नता मन की शांति व संतोष भरे मन से जीते व हार दोनों प्रकार के उम्मीदवारों को फिर जनता की सेवा में आगे बढ़ना जरूरी है।

साथियों बात अगर हम मानव को धीरज बंधाने वाले टूल्स की करें तो, दुनियां में जिसके पास प्रसन्नता, मन की शांती, संतोष भरा मन हो वो भाग्यशाली और खुश इंसान है। केवल आज की ही क्यूं वो इंसान हर दुनियां मे खुश है। मनुष्य के पास बहुत सारा पैसा हो अछी शादीशुदा जिंदगी हो अच्छे माता पिता वह चुनाव में जीत का सहारा सर पर बंधा हो लेकिन मन मे संतोष व प्रसन्नता न हो तो ऐसा व्यक्ती आज की या किसी भी दुनिया मे खुश नही हो सकता। आज की दुनिया मे नाम शोहरत पद पैसा अतिआवश्यक है। लेकीन मन का संतोष प्रसन्नता उससे भी अधिक आवश्यक है, और एक बात जो की आवश्यक है वो है हमारी सेहत, सेहत अछी हो तो व्यक्ती का जीवन आनंदमय होता है, वैसे तो कुदरत द्वारा रचित इस अनमोल खूबसूरत सृष्टि में रचनाकर्ता ने मानवीय जीवन में अनेक गुण दोषों को शामिल कर संजोया है, इसका उपयोग करने सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमता का भी सृजन कर दिया है।बस, जरूरत है अब माननीय जीव को उसे गुण-दोष सुख-दुख खुशियां-गम प्रसन्नता- दुख इत्यादि का चुनाव कर अपने जीवन को सफल और असफल बनाएं।

साथियों बात अगर हम प्रसन्नता की करें तो खुलकर हंसना, मुस्कुराना, प्रसन्न रहना, मन की प्रसन्नता खुद सृजित की हुई दवा के समान है, क्योंकि इसमें सब दुख तो नष्ट होते हैं, जीव अपने कर्म में असफल नहीं होता। बुद्धि तुरंत स्थिर रहती है। सामाजिक प्रतिष्ठा और गुणों की सुगंध दूर तक जाती है एक अलग हस्मुख व्यक्तित्व की हमारी छाया हमारे अपने परिचितों सहयोगियों पर पड़ती है। प्रसन्नता हमारा ऐसा अनमोल खजाना है, जिसे जितना लूटाएंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा, खिलखिलाते चेहरे और प्रसन्नता की आंखों की चमक मनीषियों को दुर्लभ पूंजी है, क्योंकि प्रसन्नता सुकून से जीने की कुंजी है। यह खजाना तब बढ़ता है जब हम दूसरों की खुशीयों में अपनी खुशी को समाहित करते हैं। हमें छोटी- छोटी चीजों में प्रसन्नता, सुख ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, विश्वसनीय मन के भाव की खुशी का भाव अभूतपूर्व सफलता और दूरगामी सकारात्मक परिणाम होता है आध्यात्मिकता, उदारता, परोपकार सहनशीलता सहिष्णुता इत्यादि मन की प्रसन्नता के प्रमुख स्त्रोतों में से कुछ हैं, जिनको जीवन में अपनाने की जरूरत को रेखांकित किया जा सकता है।

साथियों बात अगर हम मन की प्रसन्नता के गुण एवं लाभों की करें तो, प्रसन्नता तो व्यक्ति का मानसिक गुण है, जिसे व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन के अभ्यास में लाना होता है। प्रसन्नता व्यक्ति के अंतर्मन में छिपे उदासी, तृष्णा और कुंठाजनित मनोविकारों को सदा के लिए समाप्त कर देती है। वस्तुतः प्रसन्नता चुंबकीय शक्ति संपन्न एक विशिष्ट गुण है। प्रसन्नता दैवी वरदान तो है ही, यह व्यक्ति के जीवन की साधना भी है। व्यक्ति प्रसन्न रहने के लिए एक खिलाड़ी की भांति अपनी जीवन-शैली और दृष्टिकोण को अपना लेता है। उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता- असफलता जय-पराजय, और सुख-दुख उसके चिंतन का विषय नहीं होता। वह तो अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ता जाता है।प्रसन्नता मानवों में पाई जाने वाली भावनाओं में सबसे सकारात्मक भावना है। इसके होने के विभिन्न कारण हो सकते हैंः अपनी इच्छाओं की पूर्ति से संतुष्ट होना। अपने दिन-रात के जीवन की गतिविधियों को अपनी इच्छाओं के अनुकूल पाना। किसी अचानक लाभ से लाभांवित होना। किसी जटिल समस्या का समाधान प्राप्त होना।

साथियों बात अगर हम प्रसन्नता के लक्ष्यों की प्राप्ति की करें तो, प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेता है। यदि वह असफल भी हो जाता है तो निराश होने और अपनी विफलता के लिए दूसरों को दोष देने की अपेक्षा अपनी चूक के लिए आत्मनिरीक्षण करना ही उचित समझता है।ज्ञानीजन और अनुभवी बताते हैं कि प्रसन्नता जैसे दैवीय-वरदान से कुतर्की और षड्यंत्रकारी लोग सदैव वंचित रह जाते हैं। प्रसन्न व्यक्ति स्वयं को प्रसन्न रखकर दूसरों को भी प्रसन्न रखने की अद्भुत सामथ्य रखता है।प्रसन्नता को प्रभु-प्रदत्त संपदा समझने वाले व्यक्ति ही सदैव सुखी रहते हुए यशस्वी, मनस्वी, महान और पराक्रमी बनकर समाज और राष्ट्र के लिए आदर्श स्थापित करने में सक्षम हो सकते हैं। प्रसन्नता ही सुखी जीवन का मूल मंत्र है। प्रसन्नता हमारा अनमोल खजाना है। प्रसन्नता को ज़रूर लुटाइए फ़िर देखिए, उसका खजाना बढ़ता चला जाएगा।भलाई करना कर्त्तव्य नहीं, आनन्द है। क्योंकि वह प्रसन्नता को पोषित करता है। सबको प्रसन्न करने की शक्ति सब में नहीं होती। प्रसन्नता आत्मा को शक्ति प्रदान करती है। प्रसन्नता पूर्वक उठाया गया बोझ हल्का महसूस होता है। प्रसन्नता शब्द का प्रयोग मानसिक या भावनात्मक अवस्थाओं के संदर्भ में किया जाता है, जिसमें संतोष से लेकर तीव्र आनंद तक की सकारात्मक या सुखद भावनाएं शामिल हैं। इसका उपयोग जीवन संतुष्टिको, व्यक्तिपरक कल्याण, यूडिमोनिया, उत्कर्ष और कल्याण के संदर्भ में भी किया जाता है इसलिए हर व्यक्ति ने इस गुण अपने में समाहित कर जीवन को सफल बनाने के मंत्र को अपनाना चाहिए।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे किजीना है तो हंस के जियो एक पल भी परेशान होना ना हौसला कभी टूटे ना धीरज कभी छूटे ना।उम्मीद पर दुनियाँ चले मायूस कभी होना ना, आज हारे हैं कल जीत होगी उम्मीद कभी खोना ना।चुनावी हार जीत होती रहती है, प्रसन्नता मंन की शांति व संतोष भरे मन से जीते व हारे उम्मीदवारों को फिर जनता की सेवा में आगे बढ़ना ज़रूरी है।

क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी)
एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

ओला एस1 जेड 59,999 रुपये में लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

ओला इलेक्ट्रिक ने S1 Z के लॉन्च के साथ अपने S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। S1 Z की कीमत 59,999 रुपये और S1Z+ वेरिएंट की कीमत 64,999 रुपये है।

ओला एस1 जेड को 1.5kWh बैटरी पैक की जोड़ी द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन ओला ने एक नया रास्ता अपनाया है, वह यह कि एस1 जेड एक बैटरी पैक पर भी चल सकता है। एकल बैटरी पैक के साथ एस1 जेड की प्रमाणित रेंज 75 किमी है, जो दो बैटरी पैक के साथ 146 किमी तक बढ़ जाती है।

इसमें 3kW की अधिकतम शक्ति वाली हब-माउंटेड मोटर का उपयोग किया गया है और यह 70kph की शीर्ष गति (दावा) प्राप्त कर सकता है। ओला का दावा है कि S1 Z 4.7 सेकंड में 0-40kph की रफ़्तार पकड़ लेता है। ओला S1 Z 14-इंच के पहियों पर चलता है, जो ई-स्कूटर सेगमेंट में काफी दुर्लभ है, और ऐसा करने वाला एकमात्र अन्य भारतीय ई-स्कूटर रिवर इंडी है।

इसके अलावा कंपनी ने आयाम, वजन या चार्जिंग समय के बारे में कोई तकनीकी विवरण जारी नहीं किया है।

S1 Z में बिलकुल नई डिज़ाइन भाषा है जो कि बॉक्सी है और टॉप Z+ वेरिएंट में कुछ एक्सेसरीज़ जैसे कि आगे और पीछे लगेज रैक, एक छोटा वाइज़र और पिलियन साइडस्टेप है। S1 Z मॉडल में LCD डिस्प्ले उपलब्ध है और इसे ब्लूटूथ के ज़रिए आपके स्मार्टफ़ोन से जोड़ा जा सकता है।

59,999-64,999 रुपये की कीमत के साथ ओला एस1 जेड भारत में बिक्री के लिए सबसे किफायती दोपहिया वाहनों में से एक है, चाहे वह पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक। ओला का कहना है कि एस1 जेड की डिलीवरी मई 2025 तक शुरू हो जाएगी।

सीआरआरआई ने विकसित किया सॉफ्टवेयर, चार्जईवी शहरों में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरतों को पूरा करने में करेगा मदद

परिवहन विशेष न्यूज

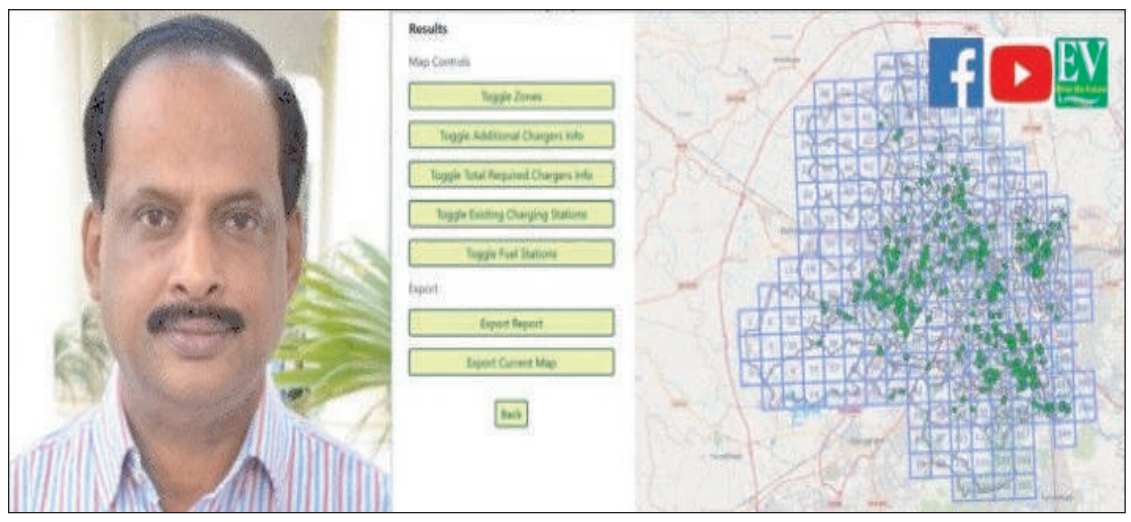

शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ ही चार्जिंग स्टेशनों की पर्याप्त व्यवस्था न होना एक बड़ी समस्या है। एक तरफ शहरों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उस समय पेट्रोल-डीजल से चलने वाले वाहनों का विकल्प बन रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए महत्वपूर्ण चार्जिंग स्टेशनों का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार करना बेहद जरूरी हो गया है।

इसके लिए केंद्र राज्य और शहरी विकास के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के स्तर पर अलग-अलग प्रयास भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई) ने एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो बताएगा कि अगले पांच से दस साल में किसी शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए किस क्षेत्र में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है।

पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकारें ईवी को बढ़ावा देने के लिए लगातार सब्सिडी दे रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी बढ़ रही है। भारत सरकार ने 2030 तक समग्र वाहन बाजार में ईवी की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इससे एक स्थायी परिवहन प्रणाली बनेगी जो उत्सर्जन को कम करेगी।

सीआरआरआई के अभिनव सॉफ्टवेयर चार्जईवी के जरिए इसे आसानी से हल किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर चार्जिंग स्टेशनों के लिए इष्टतम स्थानों को निर्धारित करने के लिए बनाया गया है। इसमें किसी शहर या क्षेत्र के जीआईएस मानचित्र के अनुसार कुछ सेकंड में चार्जिंग स्टेशनों का स्थान निर्धारित किया जा सकता है, अगले पांच या दस वर्षों में ईवी की संख्या में संभावित वृद्धि।

यह सॉफ्टवेयर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े महानगरों में यह निर्धारित कर सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों की अधिक आवश्यकता है। इस प्रक्रिया को ग्रिड मैपिंग कहा जाता है, जिसमें क्षेत्र के परिवहन विभाग से वाहनों की संख्या का अनुमान लगाकर और अनुमानित डेटा दर्ज करके भविष्य के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों का बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सकता है। जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग भौगोलिक डेटा को देखने, विश्लेषण करने, प्रबंधित करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

परिवहन योजना एवं पर्यावरण प्रभाग के मुख्य वैज्ञानिक डॉ. चालुमुरी रवि शेखर ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने से पहले दिल्ली में एक अध्ययन किया गया था, जिसका उद्देश्य ईवी के बारे में लोगों की धारणा का आकलन करना और यह जांच करना था कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर्यावरण संकट से निपटने में किस तरह से मदद कर सकती है। इसमें दोपहिया, तिपहिया और चार पहिया वाहनों के उपयोगकर्ताओं समेत 3,000 वाहन मालिकों से डेटा एकत्र किया गया, जिससे ईवी के प्रति उपभोक्ताओं के रवैये के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। जिससे दिल्ली जैसे शहर में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और स्वच्छ, अधिक टिकाऊ परिवहन विकल्पों को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है।

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के इस नवाचार की तकनीक को हस्तांतरित भी किया जा सकता है। कोई कंपनी इसे लेकर इसका व्यवसायीकरण कर सकती है। कोई नगर निगम या नगर पालिका भी इसे लेकर इसका उपयोग कर सकती है।

चार्जईवी सॉफ्टवेयर शहरों में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की भविष्य की जरूरतों का सटीक अनुमान लगाने में मददगार है। यह आने वाले समय में गेम चेंजर साबित हो सकता है। -डॉ. मनोरंजन परिदा, निदेशक, सीआरआरआई

कोमाकी ने 59,999 रुपये से शुरू होने वाली एमजी प्रो लिथियम सीरीज की लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

कोमाकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने अपनी "हर घर कोमाकी" पहल के तहत एमजी प्रो लिथियम सीरीज लॉन्च की है। 59,999 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली इस सीरीज को भारतीय घरों की दैनिक परिवहन जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

एमजी प्रो लिथियम सीरीज किफ़ायती और व्यावहारिकता के साथ-साथ दक्षता और रेंज पर ध्यान केंद्रित करती है। यह कोमाकी की हाई-स्पीड श्रेणी में आता है और इसमें 2.2 kW और 2.7 kW LiFePO4 बैटरी हैं, जो 150 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान करती हैं। इसका डिज़ाइन कार्यक्षमता और विश्वसनीयता पर जोर देता है, जिसमें एक ऑटो-रिपेयर सुविधा है जो एक सहज सवारी सुनिश्चित करने के लिए छोटी-मोटी समस्याओं को संबोधित करती है।

यह स्कूटर मोटर, बैटरी और कंट्रोलर को कवर करते हुए 3 साल या 30,000 किलोमीटर की वारंटी और चार्जर के लिए 1 साल की वारंटी के साथ आता है। इसमें ऐप-आधारित बैटरी स्वास्थ्य अपडेट भी हैं, जो उपयोगकर्ता की सुविधा और वाहन निगरानी को बढ़ाता है। एमजी प्रो सीरीज़ को लिथियम फेरो फॉस्फेट बैटरी तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है, जो बेहतर सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करता है।

लॉन्च के बारे में बात करते हुए, कोमाकी इलेक्ट्रिक की सह-संस्थापक गुंजन मल्होत्रा ने कहा, "एमजी प्रो लिथियम सीरीज़ को एक विश्वसनीय इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश करने वाले परिवारों के लिए एक व्यावहारिक समाधान के रूप में पेश किया गया है। यह दैनिक आवागमन के लिए लागत प्रभावी और उच्च प्रदर्शन विकल्प प्रदान करके भारतीय परिवारों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सुलभ और टिकाऊ बनाने के हमारे लक्ष्य के अनुरूप है।

एमजी प्रो लिथियम सीरीज़ भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करते हुए पर्यावरण के अनुकूल मोबिलिटी समाधानों को बढ़ावा देने के कोमाकी के प्रयासों को मजबूत करती है। प्रदर्शन, व्यावहारिकता और सामर्थ्य के अपने संयोजन के साथ, नए मॉडल का उद्देश्य देश भर के परिवारों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन स्वामित्व अनुभव को बढ़ाना है।

स्विच मोबिलिटी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए वर्टेलो के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान प्रदाता वर्टेलो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य अगले तीन से पांच वर्षों में 1,000 इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहन तैनात करना है, जिससे टिकाऊ और कार्बन मुक्त वाणिज्यिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।

चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में इस सहयोग को औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन, शहरी भीड़भाड़ और वायु प्रदूषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों संगठनों की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया। स्विच अपनी उन्नत ईवी तकनीक प्रदान करेगा, जबकि वर्टेलो इन वाहनों को पट्टे पर देगा और उन्हें वित्तपोषित करेगा, जिससे पूरे भारत में व्यवसायों और नगर पालिकाओं के लिए बेड़े के विद्युतीकरण में परिवर्तन को सरल बनाया जा सकेगा।

स्विच मोबिलिटी के सीईओ महेश बाबू ने कहा कि यह सहयोग भारत के वाणिज्यिक गतिशीलता परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा, ₹अपनी उन्नत ईवी तकनीक को वर्टेलो के अभिनव लीजिंग समाधानों के साथ जोड़कर, हम न केवल वाहन बेच रहे हैं बल्कि हम व्यवसायों को पूंजी की कमी के बिना टिकाऊ परिवहन अपनाने में सक्षम बना रहे हैं।₹ उन्होंने कहा कि यह साझेदारी भारत के विविध वाणिज्यिक क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लोकतांत्रिक बनाने के स्विच के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाती है।

यह साझेदारी ईवी अपनाने में पारंपरिक बाधाओं को कम करने पर केंद्रित है, विशेष रूप से उच्च अग्रिम लागत और परिचालन अनिश्चितताएं। वर्टेलो का लीजिंग मॉडल यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आकार के व्यवसाय वित्तीय तनाव के बिना भारत की बढ़ती ईवी क्रांति में भाग ले सकें।

वर्टेलो के सीईओ संदीप गंभीर ने कहा, ₹उच्च अग्रिम लागत और परिचालन अनिश्चितताओं की पारंपरिक बाधाओं को दूर करके, हम भारत की इलेक्ट्रिक क्रांति में भाग लेने के लिए सभी आकार के व्यवसायों को सशक्त बना रहे हैं।₹ उन्होंने आगे कहा कि यह साझेदारी वाहन तैनाती से कहीं आगे जाती है - यह एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के बारे में है जो वाणिज्यिक ऑपरेटरों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को स्पष्ट विकल्प बनाता है।

इन वाहनों की तैनाती से भारत के पर्यावरणीय और शहरी गतिशीलता लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है, जिससे टिकाऊ वाणिज्यिक परिवहन के लिए एक मानक स्थापित होगा।

वार्डविज़ार्ड इनोवेशन ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए एम्पवोल्ट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

परिवहन विशेष न्यूज

जॉय ई-बाइक और जॉय ई-रिक ब्रांडों के तहत परिचालन करने वाली इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी वार्डविज़ार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड ने भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्नत ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए एम्पवोल्ट्स लिमिटेड पूर्व में क्वेस्ट सॉफ्टेक (इंडिया) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों संगठनों की पूरक शक्तियों का लाभ उठाकर हरित गतिशीलता का समर्थन करने वाला एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। यह टिकाऊ परिवहन समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के साझा उद्देश्य को रेखांकित करता है।

वार्डविज़ार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए रणनीतिक स्थानों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। कंपनी प्रमुख परियोजनाओं के लिए फ्रंट-एंड पार्टनर के रूप में कार्य करेगी, जो एक कुशल ईवी इकोसिस्टम के रोलआउट में तेजी लाने के लिए वित्तीय और रसद सहायता प्रदान करेगी।

एम्पवोल्ट्स ईवी चार्जिंग उपकरण, जिसमें चार्जर और संबंधित हार्डवेयर शामिल हैं, की आपूर्ति करेगा। यह निर्बाध भुगतान प्रक्रिया और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली को सक्षम करने के लिए अनुकूलित सीएमएस सॉफ्टवेयर भी प्रदान करेगा। कंपनी वार्डविज़ार्ड के बी2बी ग्राहकों को अपनी अभिनव बैटरी एज़ अ सर्विस यानी बीएएएस पेशकशों का विस्तार भी करेगी, जिससे कुशल और स्केलेबल ऊर्जा समाधान सुनिश्चित होंगे।

वार्डविज़ार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यतिन गुप्ते ने कहा कि यह साझेदारी एक मजबूत और टिकाऊ ईवी इकोसिस्टम बनाने के उनके मिशन में एक कदम आगे है। उन्होंने कहा, ₹अनुकूलित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर समाधान विकसित करने में एम्पवोल्ट्स की विशेषज्ञता हमें अपने ग्राहकों को विश्वसनीय और कुशल चार्जिंग विकल्प प्रदान करने में सक्षम बनाएगी, जिससे उनका समग्र ईवी अनुभव बेहतर होगा। एम्पवोल्ट्स के साथ मिलकर, हम एकीकृत समाधान प्रदान करके ग्रीन मोबिलिटी में बदलाव को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो व्यवसायों और व्यक्तियों को आत्मविश्वास के साथ इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में सक्षम बनाते हैं।₹

एम्पवोल्ट्स के प्रबंध निदेशक विपुल चौहान ने कहा, ₹इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में वार्डविज़ार्ड की गहरी विशेषज्ञता और बाजार में उनकी अच्छी तरह से स्थापित उपस्थिति हमें अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि और अवसर प्रदान करती है।₹ उन्होंने कहा कि एम्पवोल्ट्स की अत्याधुनिक तकनीकों और मूल्य प्रस्तावों के साथ-साथ वार्डविज़ार्ड के मजबूत ग्राहक आधार और गतिशीलता की जरूरतों की समझ का लाभ उठाकर, एम्पवोल्ट्स अपने चार्जिंग उपकरण और सॉफ्टवेयर समाधानों को अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए तैयार कर सकता है।

यह साझेदारी दोनों कंपनियों की नवाचार को बढ़ावा देने और पर्यावरण अनुकूल गतिशीलता समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

महिंद्रा BE 6e, XEV 9e को बेचा जाएगा मौजूदा डीलर नेटवर्क के माध्यम से

परिवहन विशेष न्यूज

महिंद्रा BE 6e और XEV 9e इलेक्ट्रिक एसयूवी को अपने मौजूदा डीलरशिप के ज़रिए बेचेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव बिजनेस के अध्यक्ष वीजय राम नाकरा ने मीडिया में कहा, "हम अपने मौजूदा ऑटोमोटिव शोरूम नेटवर्क का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं ताकि हमारे खरीदार हमारे पूरे पोर्टफोलियो से चुन सकें, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी भी शामिल है।₹

महिंद्रा शोरूम में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई ब्रांडिंग के साथ विशेष स्क्रीन पर महिंद्रा की ईवी तकनीक प्रदर्शित की जाएगी।

महिंद्रा एक नया ग्राहक इंटरफ़ेस भी पेश करेगा जिसमें शुरू में बड़े शहरों में नए शोरूम शामिल होंगे। शोरूम अपने "इलेक्ट्रिक ओरिजिन" ईवी को बढ़ावा देने के लिए नई ब्रांडिंग और साइनेज पेश करेंगे, महिंद्रा अपने बोर्न-ईवी लाइन-अप के लिए बोलता है।

इन शोरूम में एक समर्पित "ईवी कॉर्नर" होगा, जिसमें छत पर एक उल्टा एलईडी स्क्रीन होगा, जो न केवल मौजूदा "ट्विन पीक्स" लोगो को प्रदर्शित करेगा, बल्कि इसके BEV पर देखा जाने वाला नया ईवी-ओनली लोगो भी प्रदर्शित करेगा। समर्पित क्षेत्र में महिंद्रा के इंग्लो ईवी आर्किटेक्चर का एक प्रक्षेपण भी होगा जो नए XEV 9e और BE 6e एसयूवी का आधार बनाता है।

अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो के लिए मार्केटिंग रणनीति के बारे में पूछे जाने पर, नाकरा ने कहा, ₹महिंद्रा के ग्राहक पहले से ही हमारे फिजिटल (भौतिक + डिजिटल) दृष्टिकोण से परिचित हैं। हम इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी के लिए इस रणनीति को और बढ़ाएंगे, एक सहज ग्राहक यात्रा बनाने के लिए दोनों चैनलों का लाभ उठाएंगे। हम अपने ग्राहक आधार की जरूरतों को समझते हैं, और हमारा दृष्टिकोण एक इमर्सिव प्री-परचेज अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूवी के नवाचार और लक्जरी को प्रतिबिंबित करेगा।"

उन्होंने आगे कहा, " हमारा लक्ष्य ग्राहकों की प्रमुख आवश्यकताओं जैसे लंबी बैटरी रेंज, विश्वसनीयता और उन्नत सुरक्षा को पूरा करना है।"

यह दृष्टिकोण टाटा मोटर्स से पूरी तरह से अलग है, जिसके पास टाटा.ईवी के रूप में ब्रांडेड ईवी खुदरा दुकानें हैं साथ ही बिक्री के बाद की सेवाओं और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग से कार्यशालाएं भी हैं।

शिक्षा में स्कूल और कॉलेज पत्रिकाओं की भूमिका

विजय गर्ग

स्कूलों और कॉलेजों से प्रकाशित पत्रिकाओं का शिक्षा में बहुत महत्व है। ये पत्रिकाएँ अक्सर छात्रों और शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखों के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान की छवि को दर्शाती हैं। स्कूल और कॉलेज की पत्रिकाएँ छात्रों में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने का एक शानदार तरीका है जो उन्हें विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाती है। छात्रों के बीच लेखन की वास्तविक क्षमता को पत्रिकाओं में काम के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है क्योंकि अन्य तरीकों से ज्यादा प्रदर्शन नहीं होगा। यहां शिक्षा में स्कूल और कॉलेज पत्रिकाओं की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही उनकी वर्तमान प्रासंगिकता पर कुछ अंतर्दृष्टि भी दी गई है: 1. रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना: स्कूल और कॉलेज पत्रिकाएँ छात्रों को उनकी रचनात्मकता को उजागर करने और खुद को अभिव्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। चाहे वह लेखन, कलाकृति, फोटोग्राफी या यहां तक कि ग्राफिक डिजाइन के माध्यम से हो, ये प्रकाशन छात्रों को अपनी प्रतिभा का पता लगाने और समुदाय के साथ अपने दृष्टिकोण साझा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। 2. समुदाय की भावना को बढ़ावा देना: आज की तेज़-तर्रार दुनिया में, स्कूल और कॉलेज पत्रिकाएँ छात्रों, शिक्षकों और पूर्व छात्रों को एक साथ लाने, एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में काम करती हैं। वे उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं, घटनाओं को उजागर करते हैं, और शैक्षणिक संस्थान के भीतर विविध प्रतिभाओं का जश्न मनाते हैं, जिससे अपनेपन और गर्व की भावना को बढ़ावा मिलता है। 3. आलोचनात्मक सोच और अनुसंधान कौशल को प्रोत्साहित करना: किसी स्कूल या कॉलेज पत्रिका के लिए लिखना केवल कागज पर कलम चलाने के बारे में नहीं है - यह आलोचनात्मक सोच और शोध में संलग्न होने के बारे में है। छात्र साक्षात्कार आयोजित करना, जानकारी इकट्ठा करना और अपने निष्कर्षों को स्पष्ट और सम्मोहक तरीके से प्रस्तुत करना सीखते हैं, कक्षा से परे विस्तारित मूल्यवान कौशल का सम्मान करते हैं। 4. डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाना: जबकि पारंपरिक प्रिंट पत्रिकाएँ अभी भी अपना आकर्षण बनाए हुए हैं, कई स्कूल और कॉलेज प्रकाशनों ने व्यापक दर्शकों तक पहुँचने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को अपनाया है। ऑनलाइन संस्करणों से लेकर इंटरैक्टिव वेबसाइटों और सोशल मीडिया चैनलों तक, ये पत्रिकाएँ डिजिटल युग को अपना रही हैं, जिससे उनकी सामग्री कभी भी, कहीं भी उपलब्ध हो सकती है। 5. वर्तमान मुद्दों और रुझानों को संबोधित करना: स्कूल और कॉलेज की पत्रिकाएँ दुनिया और परिसर में क्या हो रहा है, इसकी नब्ज पर अपनी उंगली रखती हैं। वे महत्वपूर्ण मुद्दों से निपटते हैं, चर्चाएँ शुरू करते हैं और आज के छात्रों के हितों और चिंताओं को दर्शाते हैं। जलवायु परिवर्तन और सामाजिक न्याय से लेकर पॉप संस्कृति और प्रौद्योगिकी तक, ये प्रकाशन व्यापक विषयों को कवर करते हैं जो उनके पाठकों को पसंद आते हैं। 6. छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना:

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्कूल और कॉलेज की पत्रिकाएँ छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चाहे वे पत्रकारिता, मीडिया, मार्केटिंग या किसी अन्य क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखते हों, एक पत्रिका में योगदान देने से प्राप्त अनुभव - लेखन और टीम वर्क दोनों के संदर्भ में - उन्हें सफलता की राह पर ले जाता है। तो, आपके पास यह है - शिक्षा में स्कूल और कॉलेज पत्रिकाओं की स्थायी प्रासंगिकता की एक झलक। ऐसी दुनिया में जहां जानकारी प्रचुर मात्रा में है और ध्यान देने का समय कम है, ये प्रकाशन छात्रों की पीढ़ियों को प्रेरित, सूचित और एकजुट करते रहते हैं। स्कूल पत्रिका अमर रहे! साथियों के बीच कलात्मक क्षमता को उजागर करने के लिए स्कूल और कॉलेज की पत्रिकाएँ छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त मंच हैं। कॉलेज पत्रिकाओं का एक मुख्य लाभ यह है कि लेखों के बारे में राय दर्शकों से सुनी जा सकती है क्योंकि उनमें से अधिकांश कॉलेज के अंदर होंगेस्वयं. भाषा और विषय-वस्तु जितनी सघन और गहन होगी, लेख के लेखक के बारे में जानने में दर्शकों की रुचि उतनी ही अधिक होगी। स्कूल की अधिकांश उभरती प्रतिभाओं को स्कूल पत्रिकाओं के माध्यम से अपना काम प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। स्कूल पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख शिक्षकों को युवा पाठकों को प्रेरित करने के विभिन्न अवसर भी देते हैं। शिक्षक भी छात्रों को उचित सुझाव और प्रोत्साहन देकर उनकी भाषा सुधारने में मदद कर सकते हैं। चूंकि स्कूली पत्रिकाओं में विभिन्न प्रकार का साहित्य प्रकाशित होता है, इसलिए छात्र उनमें प्रकाशन के लिए अपनी रुचि के आधार पर श्रेणियां चुन सकते हैं। अधिकांश स्कूल और कॉलेज पत्रिकाएँ प्रतिवर्ष प्रकाशित होती हैं और छात्रों को लेखों की सामग्री तैयार करने के लिए बहुत समय उपलब्ध होगा। यह छात्रों को पत्रिका में प्रकाशित होने वाली प्रतिलिपि बनाने से पहले विषयों पर शोध करने में भी मदद करता है। सामग्री को दर्शकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने के लिए उसे बार-बार लिखने में अधिक समय खर्च किया जा सकता है। तो, क्या स्कूल और कॉलेज की पत्रिकाएँ आज के शिक्षा परिदृश्य में अभी भी प्रासंगिक हैं? बिल्कुल! रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने से लेकर संचार कौशल के निर्माण और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने तक, स्कूल पत्रिकाएँ शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए, अगली बार जब आप कोई स्कूल पत्रिका उठाएँ, तो हर जगह छात्रों के शैक्षिक अनुभव को आकार देने में इसकी बहुमूल्य भूमिका को याद रखें।

नीट युजी-2025 के ऑनलाइन मोड में स्थानांतरित होने की संभावना है।

नीट युजी भविष्य की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन मोड पर स्विच कर सकता है। इस कदम का उद्देश्य परीक्षा सुरक्षा और पारदर्शिता में सुधार करना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डिजिटल बदलाव के संकेत दिए

परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और अखंडता में सुधार के लिए, नीट युजी परीक्षा को ऑनलाइन प्रारूप में स्थानांतरित करने की उम्मीद है। यह कदम नीट 2024 पेपर लीक घटना के जवाब में आया है, जिसके कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और हजारों छात्रों ने दोबारा परीक्षा की मांग की।

स्वास्थ्य मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक नवगठित स्वतंत्र निगरानी समिति को लेकर चर्चा चल रही है। इस समिति की स्थापना पेपर लीक के आरोपों से उत्पन्न चिंताओं को दूर करने और परीक्षा ढांचे को मजबूत करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए की गई थी।

राधाकृष्णन के नेतृत्व वाले पैनल ने सुरक्षा कमजोरियों को कम करने के लिए दीर्घकालिक समाधान के रूप में कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी) को चरणबद्ध तरीके से अपनाने का प्रस्ताव दिया है। इसके अतिरिक्त, इसने एक मध्यस्थ कदम के रूप में एक हाइब्रिड मॉडल की सिफारिश की है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रमुख मीडिया हाउस के साथ साक्षात्कार के दौरान नीट युजी परीक्षा को पेन-एंड-पेपर मोड से ऑनलाइन मोड में बदलने पर जोर दिया।

समिति की रिपोर्ट के अनुसार सुझाव

पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति ने नीट युजी के भविष्य के लिए कई बदलावों का सुझाव दिया। रिपोर्ट कागज-आधारित सामग्री के डिजिटल प्रारूप में प्रसारण पर भी प्रकाश डालती है। इस प्रणाली में, प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे, जबकि छात्र अपने उत्तर भौतिक शीट पर लिखेंगे।

यह दृष्टिकोण मुद्रण, भंडारण और परिवहन के दौरान कमजोरियों सहित पारंपरिक कागज-आधारित प्रक्रिया से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

समिति की रिपोर्ट का कार्यान्वयन शुरू हो गया है, जिसमें एनटीए को लगातार सलाह देने और निगरानी करने के लिए एक निगरानी समूह की स्थापना की गई है। यह समूह तीसरे पक्ष की निगरानी के रूप में कार्य करेगा। प्राथमिक ग्राहक होने के नाते स्वास्थ्य मंत्रालय से सुझावों के लिए परामर्श लिया जा रहा है।

मंत्रालय, समिति और एनटीए के साथ चर्चा के बाद, यह अत्यधिक संभावना है कि परिवर्तन कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी) की ओर स्थानांतरित हो जाएगा।

इन परिवर्तनों का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करना और सभी उम्मीदवारों के लिए एक सुरक्षित, निष्पक्ष और कुशल प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। ये सिफ़ारिशें भविष्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा कैसे आयोजित की जा सकती हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देती हैं।

हवा से भी मिलते हैं पोषक

विजय गर्ग

मनुष्य हवा से भी कुछ पोषक तत्व ग्रहण कर सकता है। सांस के जरिये लिए जाने वाले पोषक तत्व एयरोन्यूट्रिएंट्स (हवाई पोषक तत्व) कहलाते हैं, जबकि आंतों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले तत्वों को गैस्ट्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। एडवांस इन न्यूट्रिशन में प्रकाशित एक नए अध्ययन में विज्ञानियों ने लिखा है कि सांस के जरिये हमारे आहार में जिंक, मैंगनीज और आयोडिन जैसे जरूरी पोषक तत्वों को शामिल किया जा सकता है। हम प्रतिदिन लगभग 9,000 लीटर हवा अंदर लेते हैं। जीवन भर में 43.8 करोड़ लीटर हवा हमारे शरीर में पहुंचती है। खाने के विपरीत, सांस लेना कभी बंद नहीं होता। अभी तक वायु के स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में अधिकांश शोध प्रदूषण पर केंद्रित रहे हैं। हजारों सालों से विभिन्न संस्कृतियों ने प्रकृति और ताजी हवा को स्वास्थ्यवर्धक माना है। आक्सीजन तकनीकी रूप से एक पोषक तत्व है। सभी जानते हैं कि यह रासायनिक पदार्थ शरीर के बुनियादी कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

हवाई पोषक तत्व मुख्य रूप से नाक, फेफड़े और गले के पीछे छोटी रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से अवशोषित होकर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। फेफड़े आंत की तुलना में कहीं अधिक बड़े अणुओं को अवशोषित कर सकते हैं। ये अणु 260 गुना बड़े होते हैं। ये अणु रक्तप्रवाह और मस्तिष्क में अवशोषित होते हैं। सांस के जरिये ली जाने वाली दवाएं जैसे कोकेन, निकोटीन और एनेस्थेटिक दवाएं कुछ ही सेकंड में शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। वे मुंह से ली जाने वाली दवाओं की तुलना में बहुत कम सांद्रता पर प्रभावी होती हैं। इसकी तुलना में आंत एंजाइम और एसिड के साथ पदार्थों को उनके सबसे छोटे भागों में विभक्त कर देती है। आंत स्टार्च, शर्करा और अमीनो एसिड को ग्रहण करने में बहुत अच्छी है, लेकिन यह कुछ खास प्रकार की दवाओं को लेने में इतनी अच्छी नहीं है।

सांस के जरिये महत्वपूर्ण तत्वों के शरीर में प्रवेश का विचार नया नहीं है। 70 साल पहले प्रकाशित शोध से पता चला था कि स्प्रे के रूप में विटामिन बी 12 का प्रयोग इस विटामिन की कमी का इलाज कर सकता है। यह उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनमें बी12 की कमी की दर अधिक है। इनमें शाकाहारी, वृद्ध लोग, डायबिटीज से पीड़ित लोग और अत्यधिक शराब का सेवन करने वाले लोग शामिल हैं। विज्ञानियों का कहना है कि मैंगनीज और जिंक नाक में गंध को महसूस करने वाली स्नायु कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश कर सकते हैं। मैंगनीज एक आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन इसका बहुत अधिक सेवन मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है।

वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में जी-20 सम्मेलन

पिछले वर्ष भारत ने जी-20 समूह के अध्यक्ष के नाते जी-20 सम्मेलन आयोजित किया था। कई मायनों में यह सम्मेलन अभूतपूर्व था। खास तौर पर वैश्विक स्तर पर चल रहे विवादों, संघर्ष और युद्ध के वातावरण के बावजूद आम सहमति से घोषणा पत्र जारी किया गया। भारत से पूर्व इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता संभाली थी, लेकिन उस समय अंतिम घोषणा पत्र में रूस-यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में रूस की आलोचना की गई थी। जी-20 समूह, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट में अस्तित्व में आया था। भारत में जी-20 सम्मेलन बहुत धूमधाम से आयोजित किया गया। इसकी न सिर्फ भौतिक तैयारियां, बल्कि बौद्धिक तैयारियां भी पूरी गंभीरता से की गई थीं। 2023 के सम्मेलन में भारत द्वारा रूस के बारे में कुशलतापूर्वक न केवल विवादास्पद भाषा से बचा जा सका, बल्कि विश्व के समक्ष उपस्थित मुद्दों, खास तौर पर बहुपक्षीय विकास बैंकों समेत वैश्विक वित्तीय संस्थानों में पूंजीगत संरचना में बदलाव, क्रिप्टो करैंसी, वैश्विक ऋण संबंधी समस्याओं का प्रबंधन, मौसम परिवर्तन से जुड़े वित्तीयन के मुद्दे आदि, सभी पर खुली चर्चा का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

'वसुधैव कुटुम्बकम' के आधार पर 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' के ध्येय वाक्य ने वैश्विक स्तर पर चल रहे विवादों, संघर्षों, समस्याओं, मुद्दों को जैसे एक सूत्र में पिरो दिया था। ब्राजील की राजधानी रियो में सम्पन्न जी-20 सम्मेलन में इन विषयों को आगे ले जाने की एक विशेष चुनौती थी, इसलिए ब्राजील के जी-20 सम्मेलन में हुई चर्चाओं और सहमतियों को उस आलोक में भी देखना महत्वपूर्ण है। रियो, ब्राजील में सम्पन्न सम्मेलन का थीम रहा 'एक न्यायपूर्ण विश्व और एक धारणीय ग्रह'। जी-20 सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डि सिलवा ने कहा कि जी-20 सम्मेलन 2024, पिछले वर्ष की भारत की अध्यक्षता से प्रेरित रहा और भारत की सम्मेलन को आयोजित करने की कुशलता को प्राप्त करने की कोशिश इस सम्मेलन में की गई है। जी-20 सम्मेलन में ब्राजील के राष्ट्रपति ने सदस्य राष्ट्रों को अपने पर्यावरण लक्ष्यों को बढ़ाने का आह्वान किया। जी-

20 सम्मेलन के घोषणा पत्र में पर्यावरण वित्तीयन पर गतिरोध खत्म करने की जरूरत पर बल दिया, लेकिन उसके समाधान के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन देने में यह घोषणा पत्र असफल रहा। समझना होगा कि पर्यावरण वित्तीयन पर यह गतिरोध लगातार बना हुआ है, जो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और मौसम परिवर्तन जैसे अत्यंत गंभीर मुद्दों पर विकसित देशों की असंवेदनशीलता भी दर्शाता है। हालांकि सम्मेलन का घोषणा पत्र यह कहता है कि पर्यावरणीय वित्त को सभी स्रोतों से अरबों से खरबों डॉलर तक तेजी से और पर्याप्त रूप से बढ़ाना जरूरी है, इसके बारे में ठोस रणनीति या संवेदनशीलता कहीं दिखाई नहीं देती। जी-20 सम्मेलन के पहले सत्र, जिसका मुद्दा 'भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता' था, को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'भारत ने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। 55 करोड़ लोग फ्री हेल्थ बीमा का लाभ उठा रहे हैं। किसानों को 20 बिलियन डॉलर (168 हजार करोड़ रुपए) दिए।

भारत वैश्विक खाद्य सुरक्षा में योगदान दे रहा है। हाल में ही मलावी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में मदद पहुंचाई है।' प्रधानमंत्री के भाषण में पिछले सम्मेलन के थीम एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का जिक्र आया और उन्होंने इसे इस सम्मेलन के लिए भी उतना ही प्रासंगिक बताया। यही नहीं, उन्होंने जी-20 सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करने की बात को भी रखा। समझना होगा कि यह जी-20 के लिए एक मील का पत्थर था। प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध के कारण दुनिया में खाद्य, तेल और उर्वरक का संकट पैदा हुआ है और विकासशील राष्ट्रों (ग्लोबल साऊथ) पर इसका असर सबसे ज्यादा हुआ है। प्रधानमंत्री के भाषण में यह भी रेखांकित किया गया कि जी-20 की चर्चा तभी सफल होगी, जब ग्लोबल साऊथ की चुनौतियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। यही नहीं जी-20 सम्मेलन 2024 में पर्यावरणीय वित्त पर कोई ठोस बात नहीं हो पाई। पर्यावरण के विषय से जुड़े लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने संबंधी भी कोई बात घोषणा पत्र में नहीं आ पाई। गौरतलब है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने संबंधी मुद्दे पर विश्व में एक मत नहीं है। जहां भारत सरीखे देश इस बात पर जोर दे रहे हैं कि केवल कोयले के उपयोग को कम करने पर ही नहीं, बल्कि पेट्रोलियम तेल के उपयोग करने पर भी उतना ही बल दिया जाना चाहिए। लेकिन अमरीका और अरब देशों समेत अधिकांश विकसित देश भी चतुराई से केवल कोयले के उपयोग को कम करने की वकालत कर रहे हैं। उधर दुबई में आयोजित कॉप-28 सम्मेलन में देशों ने जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को कम करने संबंधी सहमति दर्शाई थी, लेकिन पर्यावरण से जुड़े कार्यकर्ताओं को लगता है कि जी-20 घोषणा पत्र में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग के बारे में बात नहीं आने से कॉप-29 में यह मुद्दा और कमजोर हो जाएगा।

महत्वपूर्ण मुलाकातें: किसी भी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का नेतृत्व केवल सम्मेलन तक सीमित नहीं रहता। सम्मेलन के साथ-साथ यह एक अवसर भी होता है कि अन्य मुल्कों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हो, कुछ अनसुलझे मुद्दे सुलझाए जाएं, मित्र देशों के साथ अपनी प्रगाढ़ता बढ़ाई जाए और विभिन्न देशों के शासनाध्यक्षों के साथ सीधी बातचीत से देश के हितों को आगे बढ़ाया जाए। इस मौके पर भारत के प्रधानमंत्री एवं प्रतिनिधिमंडल के विभिन्न सदस्यों द्वारा इस मौके का बखूबी इस्तेमाल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केवल ब्राजील के राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि इटली की प्रधानमंत्री जियोंजिया मैलोनी के साथ मिलकर प्रतिरक्षा, सुरक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर बातचीत की गई। यही नहीं अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी उनकी मुलाकात चर्चा में रही। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्ट्रॉमर के साथ भी प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, सुरक्षा, नवाचार जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई और इन मुद्दों पर मिलकर काम करने पर बल दिया गया और यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को पुनः शुरू करने की बात भी की गई। इसके अलावा फ्रांस, नार्वे, पुर्तगाल और इंडोनेशिया के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत हुई।

नार्वेजिएन प्रधानमंत्री के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। एक अन्य दिलचस्प बात भारत और चीन की द्विपक्षीय वार्ता की हुई, जिसमें चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर की बातचीत रही। भारत-चीन सीमा पर दो विवादास्पद ठिकानों पर सेनाओं के पीछे हटने के फैसले के बाद यह पहली बार हुआ कि चीन के साथ सीमा विवादों पर कोई सरकारी बातचीत हुई हो। समझा जा सकता है कि इससे भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध बेहतर होंगे और इस क्षेत्र में स्थायित्व आएगा। गौरतलब है कि मई 2020 से शुरू होते हुए पिछले 4 साल से भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी बनी हुई है। ऐसा लगता है कि पिछले सालों में जी-20 सम्मेलन का महत्व बढ़ता जा रहा है और विभिन्न देश इस सम्मेलन में शासनाध्यक्षों की उपस्थिति द्वारा प्रदत्त अवसर को अत्यंत गंभीरता से विभिन्न मुद्दों के बारे में आम सहमति बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी-20 सम्मेलन हो या ब्रिक्स सम्मेलन, वैश्विक स्तर पर इनके बढ़ते महत्व को समझते हुए कूटनीतिक विशेषज्ञ इन्हें महत्वपूर्ण वैश्विक मंच मानने लगे हैं। नए समीकरण भी बन रहे हैं। इन मंचों का उपयोग अनेक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाना चाहिए।

नर्सरी दाखिले के दौरान स्कूल जिन कारकों पर विचार करते हैं: माता-पिता के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका

यह समझने से कि नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान स्कूल क्या प्राथमिकता देते हैं, माता-पिता को अपने बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा यात्रा के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब नर्सरी दाखिले की बात आती है, तो स्कूल प्रत्येक बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारकों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करते हैं। ये कारक एक पोषणकारी और प्रभावी शिक्षण वातावरण बनाने में योगदान करते हैं जो शैक्षणिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। आइए नर्सरी प्रवेश प्रक्रिया के दौरान स्कूलों द्वारा ध्यान में रखी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण बातों पर गौर करें। संरचित वातावरण के लिए बच्चे की तैयारी स्कूलों द्वारा विचार किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक संरचित सीखने के माहौल के लिए बच्चे की तैयारी है। इसमें यह आकलन करना शामिल है कि क्या बच्चा बुनियादी दिनचर्या का पालन कर सकता है, छोटी अवधि के लिए केंद्रित रह सकता है और गतिविधियों के बीच बदलाव को संभाल सकता है। स्कूल अक्सर ऐसे बच्चों की तलाश करते हैं जिनमें जिज्ञासा, खोजबीन करने की उत्सुकता और सामाजिक मेलजोल की बुनियादी समझ हो। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास स्कूल बच्चे के सामाजिक और भावनात्मक विकास को भी प्राथमिकता देते हैं। इसमें साथियों के साथ बातचीत करने, खिलौने साझा करने और जरूरतों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की क्षमता शामिल है। एक बच्चे की भावनात्मक परिपक्वता आवश्यक है, क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि वे समूह सेटिंग में होने के उत्साह और चुनौतियों को संभाल सकते हैं। स्कूल छोटे बच्चों में स्वतंत्रता, सहानुभूति और लचीलेपन के लक्षण तलाशते हैं। स्कूल के लोकाचार के साथ माता-पिता का जुड़ाव नर्सरी दाखिले की प्रक्रिया में माता-पिता की अहम भूमिका होती है। स्कूल अक्सर यह आकलन करते हैं कि माता-पिता के मूल्य स्कूल के साथ मेल खाते हैं या नहीं, उदाहरण के लिए, हम साझेदारी दृष्टिकोण पर जोर देते हैं, जहां स्कूल और माता-पिता दोनों बच्चे के विकास में सहायता के लिए मिलकर काम करते हैं। स्कूल उन माता-पिता की सराहना करते हैं जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो अनुशासन, शैक्षणिक लक्ष्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के संबंध में संस्थान के मूल्यों को साझा करते हैं। सही स्कूल पर शोध करना और उसका चयन करना विज्ञापन माता-पिता के लिए, अपने बच्चे के लिए सही स्कूल चुनना भारी पड़ सकता है। हालाँकि, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप स्कूलों पर शोध करना महत्वपूर्ण है। माता-पिता को उन स्कूलों पर ध्यान

केंद्रित करना चाहिए जो सीखने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, शिक्षाविदों को पाठ्येतर गतिविधियों के साथ जोड़ते हैं। परिसरों का दौरा करना, अन्य अभिभावकों से बात करना और स्कूल के माहौल का प्रत्यक्ष अनुभव करना इस प्रक्रिया में आवश्यक कदम हैं। शिक्षकों के साथ जुड़ना और स्कूल के दैनिक वातावरण का अवलोकन करना बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। साक्षात्कार के लिए तैयारी साक्षात्कार के दौरान, स्कूल माता-पिता से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने बच्चे की शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और स्कूल के मिशन के बारे में अपनी समझ प्रदर्शित करें। माता-पिता को पालन-पोषण के प्रति अपने दृष्टिकोण, वे घर पर सीखने को कैसे बढ़ावा देते हैं, और स्कूल समुदाय का समर्थन करने में उनकी रुचि पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रामाणिकता और स्कूल के साथ सहयोग करने की इच्छा प्रमुख गुण हैं जिनकी स्कूल तलाश करते हैं। एक पालन-पोषण गृह वातावरण का निर्माण करना स्कूल के मूल्यों का समर्थन करने वाला एक पोषणयुक्त घरेलू वातावरण आवश्यक है। स्कूल उन माता-पिता की सराहना करते हैं जो घर पर सीखने को प्रोत्साहित करते हैं, दिनचर्या स्थापित करते हैं और सकारात्मक संचार को बढ़ावा देते हैं। माता-पिता पढ़ने, रचनात्मक खेल और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करके अपने घर के माहौल को स्कूल के मूल्यों के साथ जोड़ सकते हैं। प्रारंभिक सीखने की आदतों को बढ़ावा देना औपचारिक स्कूली शिक्षा शुरू होने से पहले, माता-पिता को विकास पर ध्यान देना चाहिएउनके बच्चों में प्रारंभिक सीखने की आदतें। निर्देशों का पालन करना, सुनने का कौशल और बुनियादी सामाजिक संपर्क जैसी सरल गतिविधियाँ बच्चों को स्कूल के माहौल के लिए तैयार करने में मदद करती हैं। खेल-आधारित शिक्षा, कहानी कहने और अन्वेषण में संलग्न होने से जिज्ञासा और सीखने के प्रति प्रेम पैदा हो सकता है। स्कूल के दृष्टिकोण को आकार देने में नेतृत्व की भूमिका मजबूत नेतृत्व किसी भी शैक्षणिक संस्थान की सफलता का अभिन्न अंग है। एक दूरदर्शी नेता यह सुनिश्चित करता है कि स्कूल न केवल शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट हो, बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और नैतिक विकास को भी बढ़ावा दे। नेतृत्व शैक्षणिक कठोरता को समग्र विकास के साथ मिश्रित करने, छात्रों को दयालु नेता और जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करने पर केंद्रित है।

वॉरेन बफे ने अपनी अरबों की संपत्ति का उत्तराधिकारी किया तय, दान किए 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के शेयर

परिवहन विशेष न्यूज

वॉरेन बफे ने बर्कशायर हैथवे के 1.1 अरब अमेरिकी डालर से अधिक के स्टॉक को चार फाउंडेशनों को सौंपने की योजना की घोषणा की है। वॉरेन बफे ने यह निर्णय कर लिया है उनकी मृत्यु के बाद उनकी 147.4 अरब अमेरिकी डालर की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा।

नई दिल्ली। निवेशक वॉरेन बफे ने सोमवार को बर्कशायर हैथवे के 1.1 अरब अमेरिकी डालर से अधिक के स्टॉक को चार फाउंडेशनों को सौंपने की योजना की घोषणा की है।

अपना उत्तराधिकारी किया तय

वॉरेन बफे ने यह निर्णय कर लिया है उनकी मृत्यु के बाद उनकी 147.4 अरब अमेरिकी डालर की संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा। हालांकि उन्होंने उत्तराधिकारियों की पहचान नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि, मेरे बच्चे इस बारे में जानते हैं और उनसे सहमत हैं। 94 वर्षीय बफे के तीन संतान हैं।

पहले बच्चों को संपत्ति देने की कही थी बात

बफे ने पहले कहा था कि उनके तीन बच्चे उनकी मृत्यु के बाद 10 वर्षों में उनकी शेष 147.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की संपत्ति वितरित करेंगे, लेकिन अब उन्होंने उनके लिए उत्तराधिकारी भी नामित किए हैं क्योंकि यह संभव है कि बफे के बच्चे इसे सब देने से पहले मर सकते हैं।

उन्होंने उत्तराधिकारियों की पहचान नहीं बताई, लेकिन कहा कि उनके बच्चे उन्हें जानते लेकिन वह चंचल हो सकते हैं। बफे ने कहा कि उन्हें अभी भी अपने परिवार में वंशवादी संपत्ति बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये विचार उनकी पहली और वर्तमान पत्नियों ने कई बार साझा किया है।

उन्होंने वर्षों में हॉवर्ड, पीटर और सूसी को लाखों देने की बात स्वीकार की।

समार्ट इंवेस्टमेंट के लिए जाने जाते है बफे

बफे समय के साथ इतनी बड़ी संपत्ति बनाने के रहस्य, चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति और बर्कशायर समूह की स्थिर वृद्धि के लिए जाने जाते हैं। बफे कई कंपनियों के अधिग्रहणों और अरबों डॉलर के एप्पल शेयर खरीदने जैसे स्मार्ट निवेशों के माध्यम से अपनी संपत्ति को बढ़ाने की बात करते रहे हैं।

बफे ने वर्षों से अपने बर्कशायर के किसी भी शेयर को नहीं बेचा और धन के मोह का भी विरोध किया और कभी भी ज्यादा लिप्त नहीं हुए। वहीं, वो बरसो से अपने पुराने ओमाहा घर में रहना पसंद करते हैं, जिसे उन्होंने दशकों पहले खरीदा था और हर दिन लगभग 20 ब्लॉक काम करने के लिए समझदार लक्जरी सेडान चलाते हैं।

बिल गेट्स के फाउंडेशन को कई बिलियन किए दान

वॉरेन बफे ने अब तक बिल गेट्स के गेट्स फाउंडेशन को 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्टॉक दान किए हैं, क्योंकि उनके मित्र बिल गेट्स ने पहले से ही अपना फाउंडेशन स्थापित कर रखा था।

बफे बर्कशायर हैथवे के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में काम करते हैं और सेवानिवृत्त होने की उनकी कोई योजना नहीं है। हालांकि उन्होंने समूह की दर्जनों कंपनियों के लिए दिन-प्रतिदिन के अधिकांश प्रबंध कर्तव्यों को दूसरों को सौंप दिया है।

क्विक रिस्पॉन्स कोड वाला नया पैन कार्ड ला रही सरकार; जानिए कैसे बनेगा और कितना रहेगा चार्ज

परिवहन विशेष न्यूज

PAN 2.0 सरकार ने पैन कार्ड को अपग्रेड करने के लिए पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। पैन कार्ड (PAN Card) अब क्यूआर कोड के साथ जारी होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि पुराने पैन कार्डधारकों को क्यूआर कोड वाला नया पैन कार्ड कैसे मिलेगा? क्या उन्हें दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा? इसके लिए कितना चार्ज देना होगा? पैन कार्ड बनवाने की क्या प्रक्रिया है?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आयकर विभाग के PAN 2.0 प्रोजेक्ट पर अपनी मुहर लगा दी है। अब लोगों को जल्द ही क्यूआर कोड सुविधा वाला नया पैन कार्ड मिलेगा, जो सरकार की महत्वाकांक्षी मुहिम डिजिटल इंडिया के मुताबिक होगा।

ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। जैसे कि पैन कार्ड क्या होता है, पैन कार्ड कैसे बनता है, अब पुराने पैन कार्ड का क्या होगा, नया पैन कार्ड क्यों बन रहा है, क्या इसके लिए कोई शुल्क देना होगा। आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं।

PAN कार्ड क्या होता है?

परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। इसका ज्यादातर इस्तेमाल वित्तीय कामकाज के लिए होता है। जैसे कि इनकम टैक्स भरना, बैंक अकाउंट ओपन करना या प्रॉपर्टी खरीदना। पैन कार्ड (Pan Card) 10 अंकों का नंबर होता है, जिसमें आपके वित्तीय लेनदेन से जुड़ी सारी जानकारियां दर्ज होती हैं। जैसे कि आपकी कितनी है, आपका कितना टैक्स भरते हैं आदि। इसमें आपके निवेश से जुड़ी पूरी जानकारियां भी होती हैं।

नया पैन कार्ड क्यों ला रही सरकार?

केंद्र सरकार ने PAN Upgrade के लिए पैन 2.0 की शुरुआत करने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, PAN 2.0 प्रोजेक्ट एक ई-गवर्नेंस पहल है जिसका मकसद पैन ऑथेंटिकेशन से लेकर पैन के इस्तेमाल को आसान और सुरक्षित बनाना है। उन्होंने कहा कि पैन कार्ड को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर 15-20 साल पुराने हैं, जिन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। PAN 2.0 के जरिए सरकार Taxpayers को बेहतर डिजिटल अनुभव देना चाहती है।

नया पैन कार्ड कैसे मिलेगा?

अगर आपके पास पहले से ही पैन कार्ड है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको नया पैन कार्ड मिल जाएगा। इसके लिए फीस भी नहीं देनी होगी। इसे आपको पता पर डिलीवर किया जाएगा। हालांकि, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको डिजिटल या फिजिकल पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।

नए पैन कार्ड में नया क्या होगा?

नए पैन कार्ड में क्यूआर कोड (QR code PAN card) जैसी सुविधाएं होंगी, जो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करेंगी। सरकार का मकसद डिजिटल इंडिया के तहत पैन 2.0 परियोजना को अधिक उपयोगी बनाना है। यह सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी अहम भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि सरकार पैन और आधार को लिंक कराने पर काफी जोर दे रही है।

पैन कार्ड कैसे बनेगा?

पैन कार्ड की बात करें, तो यह भी आधार कार्ड जितना ही महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट है। खासकर, वित्तीय मामलों में इसकी अहमियत आधार कार्ड से भी अधिक हो जाती है। इसे आप फिजिकल और डिजिटल, दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। आयकर विभाग ने पैन कार्ड को फिजिकल तरीके से बनवाने के लिए कई PayNearby और रिटेल स्टोर को PAN सर्विस एजेंसी (PSA) बनाया है। इसमें किराना स्टोर, मोबाइल रिचार्ज आउटलेट, ट्रैवल एजेंसी आदि शामिल हैं।

वहीं, पैन कार्ड को ऑनलाइन बनवाने के लिए आप इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से Instant e-PAN के लिए मुफ्त अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, फ्री ई-पैन का लाभ केवल वे एडल्ट इंडिविजुअल टैक्सपेयर ही उठा सकते हैं, जिनके पास अभी तक पैन नहीं है। उनका वैलिड आधार उनके मोबाइल नंबर से लिंक भी होना चाहिए। अगर आप पैन कार्ड खोने या डैमेज होने के बाद नया बनवाते हैं, तो आपको करीब 100 रुपये शुल्क देना पड़ सकता है।

पैन कार्ड बनवाने का प्रोसेस

- अपनी नजदीकी PAN सर्विस एजेंसी पर जाएं।
- वहां नया कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करें।
- ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर दें।
- नाम, आधार नंबर और पर्सनल जानकारी दें।
- eKYC या स्कैन-बेस्ड में से ऑप्शन सेलेक्ट करें।
- फिजिकल पैन कार्ड के लिए 107 रुपये देना होगा।
- ePAN कार्ड के लिए 72 रुपये का चार्ज रहेगा।
- पैन कार्ड पेमेंट के बाद eKYC ऑथेंटिकेशन होगा।
- eKYC ऑथेंटिकेशन के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करें।
- मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करके सबमिट करें।

इसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। इसके जरिए आप अपने पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

एन.पी.ए के जाल से बाहर आ गया बैंकिंग सेक्टर? क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े

परिवहन विशेष न्यूज

SBI के वित्तीय नतीजों से पता चलता है कि उसका शुद्ध एनपीए का स्तर सितंबर 2024 की समाप्त तिमाही में 0.58 फीसदी रहा। इसी समान अवधि पीएनबी का एनपीए 0.48 फीसद रहा। वहीं निजी सेक्टर के एचडीएफसी बैंक का एनपीए 0.41 फीसदी आईसीआईसीआई का 0.42 फीसदी पर आ चुका है। बड़े बैंकों का रिकॉर्ड यह भी बताता है कि एनपीए का स्तर पर पिछले पांच तिमाहियों से लगातार घटा है।

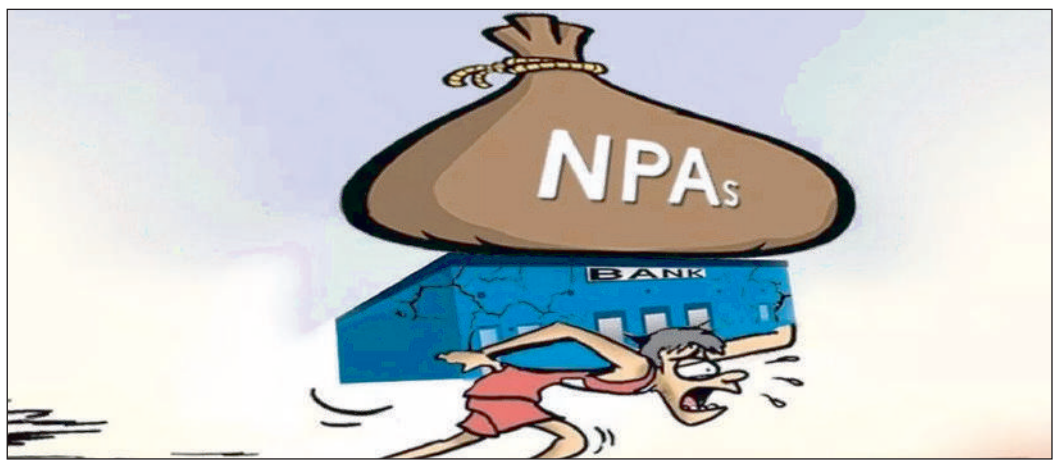

नई दिल्ली। वर्ष 2017-18 में जब भारतीय बैंकिंग सेक्टर में फंसे कर्जे यानी नॉन-परफार्मिंग एसेट्स (एनपीए) का स्तर 10 फीसद (बैंकों की तरफ से वितरित कुल कर्जे के अनुपात में) हो गया था, तब कई घरेलू और विदेशी वित्तीय एजेंसियों ने भारतीय बैंकिंग की मर्सिया पढ़नी शुरू कर दी थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। देश के सभी बड़े बैंकों का शुद्ध एनपीए का स्तर एक फीसद से नीचे आ चुका है।

क्या फिर से बढ़ सकता है एनपीए

सरकार की तरफ से जो आंकड़े सोमवार को सदन में पेश किये गये उससे भी संकेत मिलते हैं कि कर्ज वसूली का सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है। निकट भविष्य में एनपीए की समस्या के फिर से सिर उठाने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से लोकसभा में बताया गया है कि पिछले पांच वर्षों में 6,82,286 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की बकायेदारों से की जा चुकी है जिसने एनपीए के स्तर को नीचे लाने में अहम भूमिका निभाई है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया है कि "पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय बैंकों ने कुल 1,70,107 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डाला है। जबकि पिछले तीन वित्त वर्षों की बात करें तो यह राशि 5,53,057 करोड़ रुपये है। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि सरकार के स्तर पर बैंकों के बकाए कर्ज की राशि को बट्टे खाते में नहीं डाला जाता बल्कि यह कदम बैंकों के स्तर पर उठाया जाता है। साथ ही बट्टे खाते में डालने का मतलब यह नहीं है कि उक्त खाताधारकों से फिर उस कर्ज की वसूली नहीं की जाएगी। बैंक आगे भी कर्ज वसूली की प्रक्रिया जारी रखते हैं।"

बैंकों का कैसे कम हो रहा है एनपीए

सनद रहे कि बैंक जितनी बकाए कर्ज की राशि बट्टे खाते में डाल देते हैं उसका बहुत ही कम हिस्सा फिर वसूल हो पाता है। बीते मानसून सत्र में ही वित्त मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में बताया गया था कि विगत पांच वर्षों में जितनी राशि बट्टे खाते में डाली गई है उसमें से सिर्फ 18.70 फीसद हिस्सा ही बाद में वसूलने में सफलता मिली है।

हाल के हफ्तों में देश के प्रमुख बैंकों के वित्तीय नतीजों पर नजर डालें तो यह बात साफ नजर आती है कि कर्जे को बट्टे खाते में डालने से हो या कर्ज प्रबंधन बेहतर तरीके से लागू करने से हो, इनके एनपीए का स्तर काफी हद तक काबू में है।

भारतीय स्टेट बैंक का ताजा नतीजा बताता है कि उनका शुद्ध एनपीए का स्तर सितंबर, 2024 की समाप्त तिमाही में 0.58 फीसद, पीएनबी का इसी अवधि में 0.48 फीसद, निजी सेक्टर के एचडीएफसी बैंक का 0.41 फीसद, आईसीआईसीआई का 0.42 फीसद पर आ चुका है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ज्यादातर बड़े व प्रमुखों का रिकॉर्ड यह भी बताता है कि एनपीए का स्तर पर पिछले पांच तिमाहियों से लगातार घटा है।

एस्सार ग्रुप की नींव रखने वाले शशि रुइया का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

एस्सार ग्रुप के को-फाउंडर शशि रुइया का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है। शशि रुइया ने अपने भाई रवि रुइया के साथ मिलकर 1969 में एस्सार ग्रुप की नींव रखी। एस्सार ग्रुप ने भारत के टेलिकॉम सेक्टर को बदलने में अहम भूमिका निभाई। इसका कारोबार ऑयल से लेकर पोर्ट तक फैला हुआ है। रुइया अपने कारोबारी जीवन के अलावा परोपकारी कामों के लिए भी जाने जाते थे।

नई दिल्ली। अरबपति कारोबारी और स्टील, पावर, एनर्जी के साथ पोर्ट बिजनेस करने वाले एस्सार ग्रुप के को-फाउंडर शशि रुइया का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। वह 81 साल के थे। रुइया पहली पीढ़ी के उद्योगपति थे और वह अपने पीछे ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप और इनोवेशन की विरासत छोड़ गए। रुइया अपने कारोबारी जीवन के अलावा परोपकारी कामों के लिए भी जाने जाते थे।

एस्सार ग्रुप की शुरुआत कैसे की?

शशि और उनके छोटे भाई रवि रुइया ने 1969 में एस्सार ग्रुप की नींव रखी। इसमें शुरुआती निवेश 2.5 करोड़ रुपये का था। कंपनी ने एक कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग फर्म के तौर पर शुरुआत की। इसका काम पुल, बांध और बिजली संयंत्र जैसे अहम इन्फास्ट्रक्चर बनाना था।

ऑयल-टेलिकॉम सेक्टर में एंट्री

एस्सार ने 1980 के दशक तक एनर्जी सेक्टर में विस्तार कर लिया। उसने कई प्रमुख तेल और गैस एसेट्स को खरीदा। एस्सार ग्रुप ने 1990 के दशक में स्टील और टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की। उसने पहले हचिसन और फिर वोडाफोन के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर अपने टेलिकॉम बिजनेस को काफी आगे बढ़ाया। हालांकि, एस्सार 2011 में तेल और गैस, बिजली और बंदरगाहों जैसे बिजनेस पर फोकस करने के लिए टेलिकॉम सेक्टर से बाहर निकल गया।

एस्सार ग्रुप का कितना बड़ा साम्राज्य

एस्सार ग्रुप कई वित्तीय चुनौतियों से जूझने के बाद एक बड़े पोर्टफोलियो को मैनेज करता है। इसमें ब्रिटेन में 10 मिलियन टन प्रति वर्ष की रिफाइनरी, भारत और वियतनाम में विशाल हाइड्रोकार्बन भंडार और अहम रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर्स शामिल हैं। फोर्ब्स के अनुसार, 2021 में रुइया बंधुओं की नेटवर्थ करीब 18,500 करोड़ रुपये थी।

पीएम मोदी ने जताया शोक

पीएम नरेंद्र मोदी ने शशि रुइया के देहांत पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'श्री शशिकांत रुइया जी उद्योग जगत की एक महान हस्ती थे। उनके दूरदर्शी नेतृत्व और उत्कृष्टता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने भारत के कारोबारी परिदृश्य को बदल दिया। उन्होंने इनोवेशन और विकास के लिए उच्च मानक भी स्थापित किए। वे हमेशा विचारों से ओतप्रोत रहते थे। हमेशा इस बात पर चर्चा करते थे कि हम अपने देश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। शशि जी का निधन बेहद दुखद है। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।'

पत्नी के साथ लीजिए होम लोन, कई मुश्किलों से मिल जाएगा छुटकारा

परिवहन विशेष न्यूज

अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो ज्वाइंट होम लोन के विकल्प पर भी गौर कर सकते हैं। यह सामान्य होम लोन की तुलना में आसानी से मिलता है। लोन की रकम भी अधिक हो सकती है। अगर पति-पत्नी दोनों प्रोफेशनल्स हैं तो ज्वाइंट होम लोन बेहतर विकल्प रहता है। इसमें टैक्स छूट मिलती है और क्रेडिट स्कोर में भी सुधार होता है।...

नई दिल्ली। हम में से हर कोई अपना घर चाहता है। इसके लिए बहुत-से लोग लंबे समय तक पाई-पाई जोड़कर पूंजी जुटाते हैं। हालांकि, फिर भी एकमुश्त रकम देकर घर खरीदना मुश्किल होता है। ऐसे में घर खरीदने या बनवाने के लिए होम लोन का सहारा लेना सबसे आसान विकल्प बन जाता है।

होम लोन लेते समय आप ज्वाइंट होम लोन पर भी विचार कर सकते हैं। यह सामान्य होम लोन की तुलना में ज्यादा आसानी से मिलता है। इसमें लोन की रकम भी अधिक हो सकती है। अगर पति और पत्नी दोनों प्रोफेशनल्स हैं, तो ज्वाइंट होम लोन (Joint home loan benefits) उनके सबसे बेहतर विकल्प रहता है।

ज्वाइंट होम लोन किसके साथ ले सकते हैं?

ज्वाइंट होम लोन आप किसी के साथ भी ले सकते हैं। लेकिन, महिला ज्वाइंट एप्लीकेंट होने से ज्यादा फायदा मिलता है। पति और पत्नी आपस में मिलकर ज्वाइंट लोन ले सकते हैं। अगर पुरुष शादीशुदा नहीं है, तो वह माता-पिता या बहन को भी आवेदनकर्ता बना सकता है।

ज्वाइंट लोन पर मिलती है टैक्स छूट

अगर आप पत्नी के साथ ज्वाइंट होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो दोनों लोग सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स बेनेफिट (Tax savings on home loan) क्लेम कर सकते हैं। दोनों को प्रीपेमेंट करने पर ब्याज में 2 लाख की अलग-अलग टैक्स छूट मिलेगी। प्रिंसिपल अमाउंट पर भी 1 साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की टैक्स छूट ली जा सकती है।

रियायती ब्याज दर पर मिलेगा होम लोन

कई बैंक और NBFC महिला खरीदार होने की स्थिति में रियायती ब्याज दर पर होम लोन उपलब्ध कराते हैं। ये दरें अमूमन 0.05 फीसदी तक कम होती हैं। महिला का नाम होने पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में भी कुछ छूट मिल जाती है। हालांकि, ये सभी लाभ तभी मिलेंगे, जब प्रॉपर्टी में महिला भी को-ओनर रहेगी।

पहला घर खरीदने पर अतिरिक्त छूट

पहली बार घर खरीदने पर होम लोन के ब्याज पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त कटौती मिलती है। लेकिन, इसके लिए लोन की रकम 35 लाख और प्रॉपर्टी का दाम 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ब्याज चुकाने पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट लेने के लिए स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू भी 45 लाख रुपये या इससे कम ही होनी चाहिए।

क्रेडिट स्कोर में भी होगा सुधार

ज्वाइंट होम लोन लेने पर दोनों आवेदनकर्ताओं का क्रेडिट स्कोर (Credit score improvement with joint loan) भी बेहतर होता है, क्योंकि होम लोन को सबसे सिक्योर लोन माना जाता है। अगर आपका जीवनसाथी भी प्रोफेशनल है, तो उसके साथ मिलकर होम लोन लेने से ईएमआई का बोझ भी किसी एक पर ही नहीं पड़ेगा।

हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त रखें ध्यान, ये गलतियां करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा क्लेम

नई दिल्ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने मसरूफ हो गए हैं कि अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते। साथ ही, बढ़ती उम्र के साथ भी कई बीमारियां भी शरीर को घर बना लेती हैं। ऐसे में बहुत-से लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा इलाज में ही खर्च हो जाता है। इस मुसीबत से बचने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का सहारा लेना काफी अच्छा विकल्प रहता है। लेकिन, अगर आप कुछ जरूरी बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है।

हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी क्यों है?

कई बीमारियों के इलाज में काफी रकम खर्च होती है। हेल्थ इंश्योरेंस उसकी भरपाई करके आपको वित्तीय परेशानी से बचा सकता है। इससे आप मानसिक तनाव जैसी दिक्कतों से भी बच सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास चिकित्सा खर्च के लिए जरूरी रकम है। इससे आपको वित्तीय आजादी भी मिलती है। आप अपनी बचत को दूसरे जरूरी कामों में खर्च कर सकते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन की वजह

- क्लेम के साथ जरूरी दस्तावेज नहीं जमा करते हैं या उसमें कोई गलती है, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
- अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, तो उस क्लेम को भी बीमा कंपनियां अप्रूव नहीं करती हैं।
- इंश्योरेंस क्लेम को सबमिट करने की एक समयसीमा होती है, इसमें देरी करने पर भी दिक्कत होती है।
- अगर क्लेम नॉन-मेडिकल से जुड़ा है, जैसे कि दुर्घटना या आत्महत्या का प्रयास, तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
- अगर इंश्योरेंस क्लेम पॉलिसी की शर्तों के अनुसार नहीं है, तो भी कंपनी उसे रिजेक्ट कर सकती है।

पॉलिसी लेते समय इन बातों का रखें ध्यान

- इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
- पॉलिसी में क्या कवर है और क्या नहीं, इसकी जानकारी लें।
- पहले से कोई बीमारी है, तो उसका भी खुलासा करें।
- क्लेम करते समय सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा करें।
- क्लेम जमा करने की समय सीमा का पालन करें।
- पॉलिसी की अवधि समाप्त होने से पहले रिन्यू करें।
- अगर कोई उलझन है, तो बीमा एजेंट से जानकारी लें।

क्लेम रिजेक्ट होने के बाद क्या करें?

इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा के मुताबिक, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद 60 महीने लगातार प्रीमियम चुकाया है तो बीमा कंपनी आपका क्लेम खारिज नहीं कर सकती, जब तक कि धोखाधड़ी साबित न हो जाए। अगर अधूरी जानकारी के कारण क्लेम खारिज हुआ है, तो उसे सुधार कर दोबारा सबमिट करें। आपकी तरफ से कोई गड़बड़ी हुई, तो बीमा कंपनी से संपर्क करें। अगर कंपनी आपकी बात नहीं सुनती है, तो आप बीमा नियामक इरडा के पास शिकायत कर सकते हैं।

संभल की हिंसा पर उठते सवाल....

(मनोज कुमार अग्रवाल -विभूति फीचर्स)

संभल की स्थानीय अदालत के आदेश पर जामा मस्जिद में सर्वे शुरू होते ही लोग उग्र हो उठे। मस्जिद के बाहर भीड़ ने जमकर पथराव किया व पुलिसकर्मियों के वाहन जला दिए। उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी। आमने-सामने की फायरिंग में चार लोगों की मौत हुई।

इस हिंसा के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि कौन लोग हैं जो अदालत के आदेश पर अमल करने में बाधा उत्पन्न करना अपना अधिकार समझते हैं और सीधे पुलिस से टकराने के लिए पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी की तैयारी रखते हैं। संभल में पुलिस पर बरसाए गए सात ट्राली ईंट के टुकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि देश के भीतर आतंक फैलाने की साजिश और तैयारी जारी है। आखिर ये सात ट्राली ईंट के टुकड़े (करीब सात हज़ार पांच सौ ईंट) कहाँ और क्यों जमा कर रखीं गयीं थीं?

रिपोर्ट्स के अनुसार पथराव में एसडीएम, सीओ, एसपी के पीआरओ समेत 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। डेढ़ दर्जन उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। संभल बाजार बंद है । अफवाहें रोकने के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। कमिश्नर व डीआईजी संभल में ही कैंप किए हुए हैं। कमिश्नर के अनुसार नखासा क्षेत्र में भी पथराव हुआ। वहां से महिलाओं व कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु जैन (अयोध्या मामले के चर्चित वकील) ने 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पेश किया था। अदालत ने सर्वे कराने का आदेश दिया था। उस दिन वीडियोग्राफी के बाद टीम चली गई थी। दूसरे चरण का सर्वे करने रविवार सुबह सात बजे एडवोकेट कमिश्नर रमेश राघव एवं अधिवक्ता विष्णु जैन व अन्य मस्जिद में पहुंचे। क्षेत्र की नाकेबंदी कर एडवोकेट कमिश्नर डीएम और एसपी की मौजूदगी में मस्जिद की वीडियोग्राफी करा ही रहे थे कि बाहर भीड़ जुटने लगी। कुछ लोगों ने मस्जिद में घुसने का प्रयास किया। पुलिस के रोकने पर हालात बेकाबू हो गए। साढ़े आठ बजे भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ने लगी ।तभी भीड़ में से फायरिंग होने लगी। उपद्रवियों ने धार्मिक नारे लगाकर एक एसएचओ की कार व दो एसएचओ की मोटरसाइकिल समेत कई वाहन जला दिए। इसके बाद पुलिस फोर्स और भीड़ आमने-सामने आ गई। रबर बुलेट, आंसू गैस के गोले छोड़ने पर भी हालात काबू में नहीं आए तब पुलिस ने भी फायरिंग की। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार के अनुसार पुलिस पत्थरबाजी करने वालों की पहचान कर रही है। आरोपितों की पहचान के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम ने जिले में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है।

संभल हिंसा मामले में डीएम राजेंद्र पेंसिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जामा मस्जिद के सदर जफर अली साहब का भ्रामक बयान आया इसलिए हमें पीसी करनी पड़ी। उनके बयानों की डिटेलिंग हो रही है। एसपी बिश्नोई ने कहा कि जफर साहब को ना हिरासत में लिया गया , ना ही अरेस्ट किया गया । इस मामले में लगातार अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के बयान सामने आ रहे हैं। अब जामा मस्जिद सदर के वकील जफर अहमद ने कहा कि पुलिस ने गाड़ियां जलाई थीं। एसडीएम ने जबरदस्ती हौद का पानी खुलवाया। जफर ने कहा कि, लोग समझे मंदिर में खुदाई हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि जफर अहमद ने उपद्रव में मारे गए युवकों को शहीद तक कह डाला। साथ ही परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है। उनका आरोप है कि पूरा घटनाक्रम पुलिस प्रशासन का प्रायोजित प्रोग्राम था। संभल में मस्जिद के बाहर हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत समाजवादी पार्टी के सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। जिसमें उन्होंने मामले की जांच की बात की है।

यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन करती नजर आ रही है। अब पुलिस ने शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को हिरासत में ले लिया है। जफर अली ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संभल डीएम को रविवार को हुई हिंसा का जिम्मेदार बताया था। जफर अली को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। संभल जिले में हुई हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ड्रोन के फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। इस बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में हिंसा जानबूझकर भड़काई गई है। वहीं सपा के सांसद पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। संभल के विधायक के बेटे पर भी दंगा भड़काने का आरोप लगा है।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा के मामले में चार एफआईआर दर्ज की गई है और 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिंसा के दोषियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इलाके में हिंसा का असर भी देखने को मिल रहा है। शहर में एक-दो दुकानें ही खुली हुई हैं । एहतियात के तौर पर जिले में इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुए बवाल को लेकर पुलिस अब सख्त कार्रवाई कर रही है । पुलिस ने दो महिलाओं सहित 21 लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं एहतियात के तौर पर जिले में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है । स्कूल-कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। जिले में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है । संभल के आसपास के जिलों में भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। इस घटना में तीन युवकों की मौत हो गई । मृतकों की पहचान नईम और बिलाल के रूप में की गई है। बरेली, अमरोहा, रामपुर और मुरादाबाद में भी पुलिस की तैनाती की गई है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव व अन्य विपक्षी दल इस स्थिति के लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। मुस्लिम धर्म गुरू और नेता भी प्रदेश की सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं। विपक्षी दलों के नेताओं को पता है कि पुलिस या प्रशासन जो कुछ कर रहा है वह न्यायालय के आदेश पर कर रहा है। इसका प्रदेश की सरकार का प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति के कारण उपद्रवियों को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया जा रहा है।

देश संविधान द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था के अन्तर्गत चल रहा है। यह बात सभी नेताओं सहित आम जन को समझनी होगी। अगर किसी को लगता है कि कुछ गलत है तो उसे न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए न कि बवाल करना चाहिए।

वैसे अदालत के आदेश को अदालत में ही चुनौती दी जानी चाहिए। सड़कों पर उतरना और पत्थरबाजी करना, पुलिस से दो-दो हाथ करना गलत है। जिन परिवारों के बच्चे भावनाएं भड़काए जाने के कारण अपना जीवन खो बैठे हैं उन परिवारों की स्थिति शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

कानून को अपने हाथ लेने की प्रवृत्ति को रोकने का काम समाज व सरकार दोनों को मिलकर करना चाहिए। बवाल करना देशहित में नहीं। सबका साथ सबका विकास के थीम पर चलने वाली केंद्र व राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों का भरोसा और विश्वास बनाए रखना भी जरूरी है। कहीं न कहीं प्रशासन की चूक रही कि उसने एक संवेदनशील कार्रवाई से पहले पर्याप्त एहतियाती इंतजाम नहीं किए। यदि सरकार पहले से एहतियात बरतती तो संभल में टकराव की स्थिति नहीं बनती।

सवाल उठता है कि क्या प्रशासन को सर्वे से पहले मस्जिद पक्ष को विश्वास में नहीं लेना चाहिए था? क्या कुछ लोग दंगा कर सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने की साजिश रच रहे थे? क्या कुछ राजनीतिक दल इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेंकने के इच्छुक हैं? इन सब सवालों का जवाब जांच का विषय है। सरकार और प्रशासन दोनों को इन सवालों के जवाब तो देना ही होंगे। (विभूति फीचर्स)

140 करोड़ भारतीयों को जोड़ने का काम करता हैं हमारा संविधान:मुशरफ खान

संविधान के मूल कर्तव्यों का पालन ही बाबा साहेब को सच्ची श्रृद्धांजलि : वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान

आगरा,संजय साग़र सिंह। संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी मुशरफ खान ने बाबासाहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारतीय संविधान की महानता और उसकी भूमिका को उजागर किया। उन्होंने कहा, ₹हमारा संविधान 140 करोड़ भारतीयों को जोड़ने का कार्य करता है और इसका मूल उद्देश्य हर व्यक्ति को न्याय और समान अधिकार प्रदान करना है, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती मिलती है।₹

मुशरफ खान ने संविधान के रचनाकार डॉ भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा का सम्मान करते हुए कहा कि संविधान के मूल कर्तव्यों का पालन ही सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने यह भी बताया कि संविधान का सम्मान और पालन ही हमारे लोकतंत्र की शक्ति है, और इस दिन का उत्सव तभी सच्चा होगा जब हम संविधान के मार्ग पर चलें।

उन्होंने आगे कहा कि भारत में संविधान की महिमा केवल कागज पर नहीं, बल्कि इसे समझने और इसके आदर्शों को जीवन में उतारने में है। उन्होंने यह भी बताया कि संविधान के माध्यम से भारत ने सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। "हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो देश को प्रगति की दिशा में मार्गदर्शन करता है।"

संविधान दिवस के इस विशेष मौके पर मुशरफ खान ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे संविधान के आदर्शों को अपनाएं और अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें, ताकि हम 2047 तक एक विकसित भारत की ओर कदम बढ़ा सकें।

अंत में, उन्होंने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और कहा कि यह दिन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है, जिसे हमें संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण से मनाना चाहिए।

सीरवी समाज प्रीमियर लीग-7 क्रिकेट प्रतियोगिता व महिला वर्ग खेल तीसरा चरण संपन्न

परिवहन विशेष न्यूज

हैदराबाद सीरवी समाज प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के सातवें संस्करण व महिला वर्ग खेल का तीसरा चरण संपन्न हुआ। श्री आईमाताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण व आरती के पश्चात प्रतियोगिता के मुख्य प्रयोजक वंडर वाल पट्टी, समाज के गणमान्य अतिथियों एवं टीम के खिलाड़ियों के सान्निध्य में अलियाबाद स्थित सीरवी क्रिकेट ग्राउण्ड एवं श्रेष्ठा क्रिकेट ग्राउंड में प्रतियोगिता का तीसरा चरण का शुभारंभ किया गया।

आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में फ्रेन्डस क्लब के सुरेश सैणचा ने बताया कि सीरवी समाज प्रीमियर लीग-7 के तहत समाज के विभिन्न क्षेत्रों की 18 टीमों के मध्य टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता के मैच रविवार को खेले गये। महिला वर्ग के खेलों में थ्रो बॉल खेल की प्रतियोगिता संपन्न हुई तथा क्रिकेट प्रतियोगिता में तीसरा चरण का पहला मुकाबला मेडचल व रामनगर के मध्य खेला गया, जिसमें मेडचल 78 रन से विजयी रही। निलेश चौधरी को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ दि मैच से नवाजा गया। दूसरा मैच सैनिकपुरी व आईजी फ्रेंड्स कलब गजवेल के बीच खेला गया जीसमे आईजी फ्रेंड्स कलब गजवेल 53 रन विजयी रहीं मनोहर को मैन ऑफ दि मैच का पुरस्कार दिया गया। तीसरा मुकाबला नागोल व शमशाबाद के माध्य खेला गया, जिसमें शमशाबाद की टीम 5 विकेट से विजयी रही। राजत चौधरी को मैन ऑफ दि मैच का पुरस्कार दिया गया। चौथा मुकाबला कुकड़पली व टी एम जी टाइम्स के मध्य खेला गया, जिसमें टी एम जी टाइटन्स की टीम 5 विकेट से विजयी रही। मुकेश चौधरी को मैन ऑफ दि मैच का पुरस्कार दिया गया। पांचवां मुकाबला संगा रेड्डी व आईजी बिरमगुड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें संगा रेड्डी की टीम 28 रनों से विजयी रही। मुकेश वोरा को मैन ऑफ दि मैच का पुरस्कार दिया गया। छठा मुकाबला बाल नगर व ऑल विन 11 के मध्य खेला गया, जिसमें बाल नगर की टीम ने 24 रन से विजयी रही। प्रकाश सीरवी को मैन ऑफ दि मैच का पुरस्कार दिया गया। सातवां मुकाबला सिकंदराबाद व कापरा के मध्य खेला गया, जिसमें सिकंदराबाद की टीम 74 रन से विजयी रहीं। नमन चौधरी मैन ऑफ दि मैच रहे। आंठवा मुकाबला एल बी नगर व करमनघाट के मध्य खेला गया जिसमें कर्मनघाट की टीम विजेता रही। नोंवा मुकाबला आईजी गुट्ट 11 व हायतनगर के बीच मैच खेला गया, जिसमें हयातनगर की टीम विजयी रही। महिला वर्ग थ्रो बॉल बॉलीवॉल के खेल आयोजित हुए जिसमें रामनगर की टीम विजेता रही उनको सीरवी समाज प्रिमियर लीग 7 के समापन समारोह में पुरस्कृत किया जायेगा।

अवसर पर प्रतियोगिता के स्पॉनसर वंडर वाल पट्टी व समाज के गणमान्य बन्धु उपस्थित रहे। सभी मैचों का सीधा प्रसारण यू-ट्यूब पर और SSPL Application पर किया जा रहा है। सफल आयोजन में सीरवी समाज फ्रेन्डस-क्लब के सदस्य उपस्थित रहें। प्रतियोगिता का चौथा चरण 1 दिसम्बर रविवार को होंगा। फाइनल मैच 22 दिसम्बर रविवार को होगा।

सिटी माण्टेसरी स्कूलों के अन्याय के खिलाफ आंदोलन करेगी हिंद मजदूर किसान पंचायत: राकेश मणि

सुनील बाजपेई

कानपुर। सिटी मांटेसरी स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का शोषण और उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतिवर्ष सैकड़ों शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर उनके स्थान पर नये लोगों की नियुक्तियां भी की जाती हैं। यही नहीं निकाले गये अनेक कर्मचारियों के वाद न्यायालयों में 20 से 25 साल लम्बित हैं। न्याय और लाभ का इंतजार करते-करते अनेक कर्मचारी की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन अब इस अन्याय उत्पीड़न और शोषण को किसी भी हालत में सहन नहीं किया जाएगा और इसके खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए लगातार आंदोलन भी किया जाएगा। यह चेतावनी पूर्ण जानकारी देते हुए हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के महामंत्री राकेश मणि पाण्डेय ने सिटी माण्टेसरी स्कूल के आयोजनों में शामिल होने वाले जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों आदि की घोर निन्दा की है।

सिटी माण्टेसरी स्कूलों द्वारा वर्षों से शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों का शोषण करने, प्रतिवर्ष सैकड़ों शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर उनके स्थान पर नये लोगों की नियुक्तियां किए जाने का भी आरोप लगाते हुए

कर्मचारियों ,श्रमिकों के उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ अनेक आंदोलनों की सफल अगुवाई कर चुके तेजतर्रार, व्यवहार कुशल और जुझारू वरिष्ठ श्रमिक नेता हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के महामंत्री राकेश मणि पांडेय ने यह भी बताया कि कई बैंचों और न्यायालयों की पीठ द्वारा आदेशित किए जाने यहां तक कि श्रम विभाग से लेकर सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी सैकड़ों शिक्षक कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान आज तक नहीं किया गया।

सिटी मांटेसरी स्कूलों में शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का तरह-तरह से शोषण और उत्पीड़न किए जाने का भी आरोप लगाते हुए वरिष्ठ श्रमिक नेता राकेश मणि पांडेय बताया कि यही नहीं इसी लाभ का इंतजार करते करते ना जाने कितने कर्मचारी काल कलवित भी हो चुके हैं।

अपने पक्ष में दबाव बनाने के लिए सिटी मोंटेसरी स्कूलों द्वारा साम ,दाम , दण्ड, भेद की नीति के तहत देश प्रदेश के राजनेताओं न्यायाधीशों और राजपत्रित अधिकारियों को माध्यम बनाए जाने जैसे तरह तरह के हथकडे अपनाने का भी आरोप लगाते हुए श्रमिक कर्मचारियों के उत्पीड़न, शोषण और समस्याओं के खिलाफ जुझारू तेवरों वाले कर्मचारी नेता राकेश मणि पाण्डेय ने बताया कि जो सीएमएस स्कूल एक अरब बच्चों के भविष्य सुधारने की बात करते हैं। वही निकाले गये ,गार्डों , ड्राइवरों ,शिक्षकों तथा कर्मचारियों के बच्चों को स्कूल से निकाल कर शिक्षा से वंचित कर देते हैं।

न्यायपालिका, कार्यपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनेताओं आदि द्वारा

आयोजनों में शामिल होकर श्रम कानून न मानने वाले सिटी माण्टेसरी स्कूलों की सराहना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हिन्द मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय सचिव एवं उत्तर प्रदेश के महामंत्री राकेश मणि पाण्डेय ने दावा किया कि यदि सिटी माण्टेसरी स्कूल के स्थापना से लेकर विभिन्न आयोजनों व उसके मध्य हुए अस्वभाविक मौतों और अन्य स्थितियों की जांच की जाये तो ना केवल एक खतरनाक पहलू उभर कर सामने आयेगा बल्कि सरकार की मजदूर विरोध सोच भी उजागर होगी।

झारखंड की मुख्य सचिव ने संविधान दिवस पर दिलाई शपथ

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड

रांची , झारखंड मंत्रालय परिसर में मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी तथा सचिव बंदना डाडेल द्वारा विभिन्न मंत्रालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को संविधान दिवस पर शपथ दिलाई गयी । इसके साथ ही झारखंड के सभी जिलों के उपायुक्त एवं वरीय पदाधिकारियों द्वारा संविधान निमित शपथ दिलाने का कार्यक्रम का आयोजन हुआ ।

हम बताते चलें कि 2015 के पहले 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता रहा। देश के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को फैसला लिया गया कि जनता को संविधान का उद्देश्य बताने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा, फिर संविधान दिवस मनाये जाने लगा । आज भारतीय सामाजिक परिवेश में इसकी अहमियत और बढ़ गयी है ।

हेमंत ने प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण समारोह में आने का दिया न्यौता

कार्तिक परिच्छा , स्टेट हेड

सरायकेला , झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सपत्नीक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से दिल्ली जाकर मिले । उन्होंने आगामी 28 नवम्बर को झारखंड के नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया है । झारखंड विधानसभा चुनाव में आशातीत सफलता के बाद झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमित शाह एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सह आप नेतृत्वकर्ता अरविंद केजरीवाल से भी पत्नी कल्पना सोरेन संग मुलाकात की है । उन्हें आगामी शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया है ।

मुहब्बत को याद करते है

ये हम उनकी ही मुहब्बत को याद करते है,
हुई जो गलती उसे भूलने की बात करते हैं।
प्यार तो हम दिन-रात तुझे ही यार करते हैं,
आ जाओ फिर एक बार मुलाकात करते हैं!
जो आगे दूरियां निकटता की बात करते हैं।

ये हम उनकी ही मुहब्बत को याद करते है,
हुई जो गलती उसे भूलने की बात करते हैं।
यार तुम्हें ही मनाना है अपने घर वालों को,
हमें तो डंडे ना पड़े उसकी ही बात करते हैं!
धैर्य और साहस कैसे रखें वहीं बात करते हैं।

ये हम उनकी ही मुहब्बत को याद करते है,
हुई जो गलती उसे भूलने की बात करते हैं।
अब तो मेरे सब्र का बांध भी टूटा जा रहा है,
हम ही आपके अभिभावकों से बात करते हैं!
दे दो आपकी परी हम भी उसे प्यार करते हैं।

ये हम उनकी ही मुहब्बत को याद करते है,
हुई जो गलती उसे भूलने की बात करते हैं।
इतना साहस न था सिर्फ फरियाद करते हैं,
हमसे जो बन सकेगा हम वही बात करते हैं!
लाखों में एक है इसलिए हम मांग करते हैं।

संजय एम. तराणेकर

पुर्व केंद्रीय मंत्री बिश्वेश्वर टुडू का राजनीति भविष्य क्या? कौन इसी का जिम्मेदार

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुवनेश्वर: पूर्व केंद्रीय मंत्री बिश्वेश्वर टुडू बनबासी आश्रम बिद्यालय और एक्केल स्कूलों के संपर्क में आए और उन्होंने आदिवासी छात्रों की भलाई के लिए काम किया। बाद में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और राजनीति में शामिल हो गए , अभियान की शुरुआत

में अपना विजय पताका फहराया। जब वे वहां थे, तो उन्हें वीजेडी से काफी परेशानी हुई। इस कारण उनकी पहचान एक मध्यम वर्ग के रूप में हुई और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उन्होंने ओडिशा और भारत में विभिन्न सुधारों के लिए काम किया। इसमें केवल एकलब्य स्कूल और दूसरा स्तर होता है। 2024 के चुनाव में बीजेपी के किसी सांसद/विधायक का टिकट नहीं मिला। हालाँकि, उन्होंने पार्टी की इच्छा को स्वीकार किया। ओडिशा में पार्टी कैसे शासन मे आएंगे , इसके लिए उन्होंने पूरे ओडिशा में प्रचार किया, हाल ही में उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव में दो महीने तक प्रचार किया, उनकी राजनीति धीरे-धीरे अंधकार की ओर बढ़ रही है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है !

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओड़िशा में तीन दिवसीय पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सम्मेलन में भाग लेंगे

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओड़िशा में तीन दिवसीय पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सम्मेलन में भाग लेंगे। कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा, इसीलिए वह ओडिशा की 3 दिवसीय यात्रा पर आएंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 तारीख को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए ओडिशा आएंगे।वह 30 और 1 दिसंबर को डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे।

कानून मंत्री से पहले डीजीपी वाई. बी खुरानिया ने बताया कि प्रदेश में 29 तारीख से होने वाली तीन दिवसीय डीजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल होंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी शामिल होंगे। इसके अलावा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी इसमें हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य की सुरक्षा पर भी चर्चा होगी।

पहले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वहां सरकार के विभिन्न एजेंडों पर चर्चा होगी । इसके लिए अतिथि आवास, बैठक स्थल पर सभी सुरक्षा उपाय किये जायेंगे। ओडिशा पुलिस की ओर से सुरक्षा संबंधी सभी कदम उठाए गए हैं ।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023